|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **भाषण**  *प्रमुख क्षेत्रों को डिकोड करना जो घरेलू आर्थिक सुधार को बनाए रख सकते हैं* **- REITs, InvITs,** *डेटा सेंटर और* **NBFCs**  यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रातःकालीन बेला में मुझे आप के समक्ष REITs व InvITs के विषय पर सम्बोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। REITs व InvITs घरेलू आर्थिक सुधार में प्रमुख क्षेत्रों का रूप अदा कर सकते हैं।  किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, विशेष रूप से भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की आवश्यकता अत्यधिक है। इस तरह की संपत्ति बनने के बाद और निर्मित होने के बाद अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी भारी गति प्रदान होती है। एक अर्थव्यवस्था की अधिरचना, आखिरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एसेट्स पर निर्मित होती है। देश और अर्थव्यवस्था के लिए वापसी कई गुना हो सकती है।  हालांकि, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दोनों ही कई डेवलपर या प्रायोजकों के लिए अभिशाप रहे हैं।  इनमें शामिल जोखिमों को समझना काफी आसान है:   * ऐसी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने का जोखिम, * समय पर पूरा न होने पर लागत बढ़ जाती है * संपत्ति के लिए कुल खरीद या तैयार उपयोगकर्ताओं या पट्टेदारों की पहचान करना और उन्हें सुरक्षित करना * विभिन्न परियोजनाओं के नकदी प्रवाह को मिलाना और अलग-अलग हितधारकों से समझौता करना * पर्यावरण के कारणों या उचित पुनर्वास के बिना विस्थापन के कारण स्थानीय नागरिकों या गैर- सरकारी संगठनों के विरोध से उत्पन्न चुनौतियाँ, जो की न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाती हैं और समय और लागत में वृद्धि में योगदान करती हैं।   डेवलपर्स स्वयं परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और यदि ऐसी कई परियोजनाएं हैं, तो प्रतिकूल प्रचार या पूंजी बाजार के अनुकूल नहीं होने के कारण पूर्ण परियोजनाओं के लिए कोई टेकआउट नहीं होता।  ये जोखिम अक्सर वित्तपोषकों को प्रेषित किए जाते हैं चाहे वे बैंक हों या बांड धारक। यहां तक ​​​​कि अंतिम क्रेडिट चक्र के रूप में, बैंकों ने या तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने या कमर्शियल रियल एस्टेट उधार देने की जगह खाली कर दी या केवल टियर 1 नामों पर ध्यान केंद्रित किया। इस लिहाज से REITs और InvITs के लिए SEBI के नियमों का आगमन काफी समय पर हुआ था। ऋण देने के लिहाज़ से, यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कंपनियों के निर्माण के पूरक था।  REIT और InvIT निवेशकों के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति वर्ग में तुरंत जुड़ गए, किसी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि या संचालन के बिना, REITs के मामले में व्यावसायिक रियल एस्टेट और InvITs के माध्यम से अवसंरचना संपत्ति से विशेष रूप से एक्सपोजर और मुनाफा मिला।  REITs और InvITs की डिजाइन और अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि ऐसे व्यावसायिक ट्रस्टों के भीतर रखी गई कम से कम 80% संपत्ति राजस्व उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए (जब सार्वजनिक रूप से जारी और सूचीबद्ध InvITs और सभी REITs - मानदंड निजी तौर पर रखे गए और सूचीबद्ध InvITs के लिए थोड़े अलग हैं)। इस प्रकार, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के मामले में अभी तक प्रोजेक्ट पूरा होने का जोखिम या ऑफटेकर्स का पता नहीं होने का जोखिम, और इसी तरह, पट्टेदारों और किरायेदारों वाली रियल एस्टेट के जोखिम निवेशकों के लिए काफी कम हो जाते हैं।  डेवलपर के लिए, इसकी इक्विटी हिस्सेदारी का एक तैयार टेकआउट है, जो ड्रॉइंग बोर्ड पर मौजूद या प्रगति पर काम करने वाली अन्य परियोजनाओं की ओर प्राप्तियों के पुनर्चक्रण की अनुमति देता है। एक परियोजना प्रबंधक के साथ-साथ REITs/InvIT के निवेश प्रबंधक के माध्यम से संचालन के प्रबंधन के कारण एक सतत सहयोग है।  निवेशकों के लिए, एसेट्स और उनकी इनकम स्ट्रीम्स का मूल्यांकन करने और फिर REIT/InvIT संरचना के माध्यम से उनके स्वामित्व में भाग लेने का एक उचित अवसर है। डेवलपर एसेट्स के रखरखाव और संचालन का प्रबंधन करता है और अपनी विशेषज्ञता उसी के लिए उपलब्ध होने वाली उचित विशेषज्ञता का सेवा प्रदान करता है। भुगतान REITs और InvITs को रेखांकित करने वाले एसेट क्लास को दर्शाता है, चाहे वह ब्याज, लाभांश या अन्य वितरण के रूप में हो।  इसलिए यह पुष्टि की जा सकती है कि REITs और InvITs (संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए) एक उपयुक्त संरचना बन गए हैं, और संक्षेप में:   * आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के चरण को देखते हुए, REITs और InvITs से देश में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनर्वित्त के लिए एक उपयुक्त संरचना प्रदान करने की उम्मीद है। * REITs और InvITs, एक निवेश वाहन के रूप में, निम्न में सहायता कर सकते हैं:   ○ मौजूदा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए व्यापक और दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करना।  ○ नई रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में पुनर्निवेश के लिए मौजूदा डेवलपर पूंजी को मुक्त करना।  ○ लंबी अवधि की कम लागत वाली पूंजी के साथ मौजूदा उच्च लागत वाले ऋण का पुनर्वित्त/टेकआउट करना और बैंकों को ऋण जोखिम मुक्त/कम करने में मदद करना, और इस तरह नई फंडिंग आवश्यकताओं के लिए बैंक हेडरूम बनाना।   * ऐसी कई रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, जिनका फंड पूरी तरह से पूरी हो चुकी/पर्याप्त रूप से पूरी हो चुकी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अटका हुआ है, जिसका इस्तेमाल देश में और अधिक रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जा सकता है। REITs और InvITs ऐसी संपत्तियों को पुनर्वित्त करने के साथ-साथ एक निवेश विकल्प बनाने के लिए सक्षम वाहन हो सकते हैं जो अन्यथा इस तरह के जोखिम के इच्छुक निवेशकों के लिए संभव नहीं हो सकता है। * REITs और InvITs को भविष्य में एक ही वाहन में परियोजनाओं को जोड़ने की अनुमति है ताकि निवेशक विविधीकरण के साथ-साथ अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि से लाभान्वित हो सकें। REITs और InvITs भारतीय रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। REITs और InvITs निवेशकों को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने में सक्षम बनाएंगे। * REITs और InvITs से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और संपत्ति से आय के प्रबंधन और वितरण में शासन के उच्च मानकों को लाने की भी उम्मीद है जिससे कि निवेशकों की रुचि को आकर्षित किया जा सके।   चूंकि REITs और InvITs को सीधे या HoldCos या SPVs के माध्यम से लाभ उठाने की अनुमति है, यूनिट धारकों की उचित स्वीकृति के साथ जब इस तरह का उत्तोलन विशेष स्तर का होता है, जबकि एक निश्चित स्तर पर कैप किया जाता है, नई परियोजना के विकास के लिए उचित धन उगाहने और उपयोग की अनुमति देता है। या संचालन और रखरखाव के लिए। फंड जुटाने के लिए आय पैदा करने वाली संपत्तियों से नकदी प्रवाह और रेटिंग की आवश्यकता को देखते हुए, इस तरह जारी किया गया ऋण निश्चित आय वाले निवेशकों के लिए भी आकर्षक है।  विनियामक दृष्टिकोण से, REITs और InvITs के डिजाइन और संरचना ने निवेशकों को भाग लेने के लिए नई एसेट क्लास उपलब्ध कराने के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा किया है, प्रारंभिक और निरंतर आधार पर उचित ज्ञान और प्रकटीकरण के साथ। साथ ही, वर्षों से, अधिक से अधिक निवेशकों को REITs और InvITs में भाग लेने में सक्षम बनाने के उपाय भी किए गए हैं, प्रारंभिक सदस्यता में कमी को 10,000/- रुपये तक कम किया जा रहा है और ट्रेडिंग लॉट एक इकाई है।  तो REITs और InvITs के लिए आगे क्या है?   1. भले ही खुदरा भागीदारी सक्षम है और हो भी रही है, यह REITs और InvITs के लिए एक संघ में सम्मिलित होने का सही समय है। जिस तरह AMFI - म्यूच्यूअल फण्ड इंडस्ट्री का संघ - म्युचुअल फ़ंड को एक एसेट क्लास के रूप में प्रचार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । 'म्यूचुअल फ़ंड सही है' अभियान के बारे में सोचें, कोई REITs के एसोसिएशन की परिकल्पना 'REITs राइट है!' कहकर कर सकता है। कॉपीराइटर बनने के बजाय (और उन कौशलों पर निर्णय लेने के लिए), जो मैं नोट करूंगा वह यह है कि व्यक्तिगत रूप से किसी भी REIT और InvIT के लिए संपूर्ण संपत्ति वर्ग को बढ़ावा देना मुश्किल हो सकता है, जबकि ऐसा करने के लिए एक संघ बेहतर स्थिति में हो सकता है। उद्योग के विचारों को प्रस्तुत करना या किसी संघ के माध्यम से विनियामक मार्गदर्शन देना भी अधिक अनुकूल हो जाता है। 2. डेवलपर प्रायोजक के साथ घनिष्ठ संबंध को देखते हुए, चाहे प्रारंभिक संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण या बाद में, और ऐसी संपत्तियों को डेवलपर या उसके सहयोगियों द्वारा बनाए रखा और प्रबंधित किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करें कि सभी व्यावसायिक संबंध एक हाथ की दूरी पर हैं आधार और यह सुनिश्चित करना कि कोई संबंधित पार्टी लेनदेन REIT या InvIT के प्रतिकूल नहीं है और तदनुसार यूनिट धारकों के लिए, REITs और InvITs में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। रेटिंग एजेंसियों के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशकों, मूल्यांककों और लेखापरीक्षकों के लिए, ये अंतर्संबंध उचित शर्तों पर होने के कारण मूल्यांकन और निर्णय लेने का हिस्सा बनने चाहिए। 3. उत्तोलन- मैंने REITs और InvITs की बैंकों से उधार लेने या बांड जारी करने की क्षमता के बारे में पहले उल्लेख किया था - जो कि संपत्ति से नकदी प्रवाह से सेवित है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे मौजूदा REITs और InvITs स्केल करेंगे और संतुलित रिटर्न प्रदान करने में सक्षम होंगे। यह देखते हुए कि REITs और InvITs के गठन से पहले भी इस तरह के बहुत से उत्तोलन को अनुबंधित किया गया है, और / या दीर्घकालिक प्रकृति का है (कुछ पुनर्भुगतान 15-20 वर्ष के कार्यकाल तक फैला हुआ है), यह देखने की आवश्यकता है कि यूनिटधारक कैसे हितों की सबसे अच्छी तरह से रक्षा की जाती है और यदि इस संदर्भ में प्रायोजकों और यूनिट धारकों के हितों के उचित संरेखण को सुनिश्चित करने का कोई तरीका है। 4. इसके साथ ही हम बंधक REITs के निर्माण का पता लगाने और आकार देने के इच्छुक हैं - जो आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियों - आरएमबीएस और सीएमबीएस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काम कर सकते हैं - या अनिवार्य रूप से, स्थायी पूल उपलब्ध करा सकते हैं ऐसे बंधकों के प्रतिभूतिकरण के लिए पूंजी, और उन्हें निवेशकों को उपलब्ध कराना। हम जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी करने की उम्मीद करते हैं और इसे चालू करने पर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। 5. यह भी समझा जाता है कि निश्चित आकार और रूप की कमर्शियल रियल एस्टेटको कुछ भिन्नात्मक रियल एस्टेट निवेश प्लेटफार्मों द्वारा पैक और वितरित किया जा रहा है। ये अनियंत्रित उत्पाद हैं, नियामक परिधि के बाहर हैं और संघर्षों से व्याप्त हो सकते हैं, निवेशकों के लिए बाहर निकलने के विकल्पों की कमी है, और इसमें कानूनी जोखिम निहित हैं। इस तरह के आंशिक रियल एस्टेट निवेश प्लेटफार्मों पर और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक करीब से देखने की जरूरत है। यदि इसे विनियामक परिधि के भीतर लाया जाना है, तो वर्तमान REITs नियम एक अच्छा ढांचा प्रदान करेंगे, जो कि कुछ बदलावों के साथ, इस तरह के आंशिक रियल एस्टेट निवेश प्लेटफॉर्म पर लागू हो सकते हैं। हम एक परामर्श पत्र जारी करने पर विचार करेंगे और इसे संबोधित करने पर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। 6. शहरी बुनियादी ढांचे और नगर निगमों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है - वित्त मंत्री द्वारा इस वर्ष के बजट भाषण में इस रेखांकन का उल्लेख करने के साथ - एक तत्व जिस पर हम विचार कर रहे हैं, वह InvITs के निर्माण को सक्षम कर रहा है जो नगर निगमों से शहरी आधारभूत संरचना संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं। अन्य सार्वजनिक निजी भागीदारी कैसे की गई है या नगर निगम के साथ एक रियायत समझौते के माध्यम से किया गया है। नगरपालिका वित्त को मजबूत करने और सार्वजनिक निवेश के लिए राजस्व पैदा करने वाली संपत्तियों को जारी करने के अलावा, यह नगर पालिकाओं को आगे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। 7. हाल ही के कर प्रस्ताव ने उद्योग की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की है जो कराधान के मामले को स्वीकार करता है, भले ही यह प्रस्तावित अन्य स्रोतों से आय के बजाय पूंजीगत लाभ के शीर्षक के तहत हो। जबकि इस पर विचार करना MoF का काम है, कृपया ध्यान दें कि REIT या InvIT द्वारा प्राप्त अंतर्निहित प्रवाह यूनिटधारकों को आगे वितरण से मेल खाते हैं। इसलिए ब्याज के रूप में प्राप्त धन आवश्यक रूप से ब्याज के रूप में भुगतान किया जाता है, और लाभांश के रूप में प्राप्त लाभांश का भुगतान किया जाता है। इस तरह के मेल खाने वाले प्रवाह आरईआईटी और इनविट को एक पास-थ्रू इकाई बनाते हैं, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। 8. REITs और InvITs के संबंध में शासन पर ध्यान केवल IM - निवेश प्रबंधक को देखने तक सीमित नहीं होगा। होल्डकोस/एसपीवी और परियोजना प्रबंधक या प्रबंधक में भी सुशासन की अपेक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट आश्वासन प्रक्रिया के रूप में आईएम के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उचित निगरानी इन संस्थाओं तक विस्तारित होनी चाहिए। प्रायोजक और प्रायोजक नियंत्रित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी के लेन-देन के बारे में सावधान रहना, और यह सुनिश्चित करना कि ये आर्म्स लेंथ पर हैं और प्रबंधन और उनके पर्यवेक्षकों सहित स्वतंत्र निदेशकों पर शोषणकारी या प्रतिकूल या अनुचित झूठ नहीं है। इससे यूनिटधारकों की उचित सुरक्षा होती है, जो आईएम में बोर्ड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला बना रहना चाहिए। 9. निवेशक इस एसेट क्लास में आ गए हैं, और उनमें से कई वैश्विक निवेशक हैं जिनमें सॉवरेन वेल्थ फंड, विदेशी पेंशन फंड और अन्य दीर्घकालिक निवेशक शामिल हैं। REITs और InvITs के साथ ऐसे निवेशकों की परिश्रम और जांच और व्यापक भागीदारी आत्मविश्वास को प्रेरित करती है, जिसके बारे में ऐसे निवेशकों को जागरूक होना चाहिए। ऐसे निवेशकों को संस्थागत निवेशकों के लिए स्थापित प्रबंधन संहिता का पालन करना चाहिए। कई और निवेशक इस स्मार्ट मनी का अनुसरण करेंगे और यूनिटहोल्डर के हस्तक्षेप या आत्म-व्यवहार की मांग करने वाली स्थितियों में निष्क्रियता या अनजानता से स्मार्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो उन्हें अन्य यूनिटहोल्डर्स से आगे रखता है। 10. अंत में, कई विनियमित संस्थाएं REITs और InvITs का समर्थन और सेवा करती हैं, जिसमें ट्रस्टियों के रूप में गठित डिबेंचर ट्रस्टी, REITs और InvITs द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों की रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिपॉजिटरी (जहां इकाइयां डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखी जाती हैं) और स्टॉक एक्सचेंज (जहां इकाइयां सूचीबद्ध हैं)। इस तरह के प्रत्येक मध्यस्थ को अपनी सेवा की प्रकृति के लिए आवश्यक भूमिका निभाते हुए पेशेवर, स्वतंत्र और निंदा से ऊपर की सेवा प्रदान करनी चाहिए। यह REITs और InvITs पर एक चेक और बैलेंस के रूप में कार्य करता है और यूनिटधारकों के हितों की रक्षा करता है।   इसके साथ मैं उन प्रमुख क्षेत्रों को डिकोड करने के लिए चर्चा को वापस लेता हूं जो घरेलू आर्थिक सुधार को बनाए रख सकते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए सत्रों की सराहना करते हैं कि विनियामक और निवेशक अपेक्षाओं को लघु, मध्यम और दीर्घकालिक में पूरा किया जाए।  धन्यवाद!  **2050** में कॉर्पोरेट भारत की स्थिति और नियामक रुझान  प्रमोद राव  आप सभी को गुड मॉर्निंग। कॉन्फ्लुएंस 2023 - मेगा कॉरपोरेट कॉन्क्लेव में आना और 2050 में कॉर्पोरेट इंडिया की स्थिति और नियामक रुझानों पर बोलना खुशी और सौभाग्य की बात है।  मुझे आज दर्शकों में प्रोफेसर एनएल मित्रा के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, जो एनएलएस बैंगलोर में मेरे प्रोफेसर थे और बाद में इसके वाइस चांसलर थे, जिन्होंने हमें प्रमुख विषयों में बैंकिंग, बीमा, और कानून, लेखा और वित्तीय प्रबंधन पढ़ाया। मेरा पेशेवर जीवन, और भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में कानून के विकास में सीखने और योगदान करने के लिए जीवन में एक दृष्टिकोण रखना सिखाया।  भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक उत्साही पर्यवेक्षक होने के नाते मैं और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में यह बोल सकता हूँ (अगर मेरी स्मृति ठीक से काम करती है) कि नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर (पांच साल के कानून कार्यक्रम) में दूसरा लॉ स्कूल है। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को कवर करने के लिए कवर पढ़ा जिसे लॉ स्कूल ने सब्सक्राइब किया और पाया कि मैं कम से कम पहले कुछ वर्षों में पढ़ने वाला अकेला व्यक्ति था। वह पढ़ने की आदत - चाहे प्रिंट की हो या सोशल मीडिया की - मैं आप सभी को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मिलेनियल्स को देखते हुए, जो दर्शकों में हैं, YouTube, OTT , पॉडकास्ट या ऑडियोबुक सुनना भी ठीक वैसे ही काम करता है।  इस तरह के अवलोकन, पढ़ना, सुनना और देखना मुझे 2050 में प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, और जैसे कि हमें 2050 तक टेलीपोर्ट किया गया है, इस प्रकार हैं:   1. कॉरपोरेट इंडिया अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों के लिए अच्छी तरह से तैयार है। यह समझता है कि प्रतिस्पर्धी होने और सभी हितधारकों का सम्मान करने में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। इस तरह के हितधारकों में इसके अपने कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता, साथ ही इसके ग्राहक, नियामक और उन देशों की सरकारें शामिल हैं जिनमें भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का संचालन होता है। दर्शकों में छात्रों के लिए- *यह ज्ञान और हितधारकों और बाजारों की समझ - हितधारकों को कौन सी प्रेरणाएँ प्रेरित करती हैं और ऐसे हितधारकों से निपटने में निष्पक्षता क्या है। हितधारकों के साथ उचित व्यवहार* 2. कॉरपोरेट इंडिया अपने बोर्ड द्वारा अच्छी तरह से शासित है, जो विविध है और उन बाजारों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें यह संचालित होता है। विविधता दोनों लिंग और दृष्टिकोण की भी है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आती है, और विभिन्न किस्सों को सह-चयन करने में सक्षम है। जिसमें समाज शामिल है। इस तरह की विविधता जो पूंजी बाजार नियामक द्वारा महिला निदेशकों और बाद में महिला स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के रूप में शुरू हुई थी, अब नियामक लागू होने के कारण नहीं की जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स इसे समाज के प्रति चिंतनशील होने के लिए एक व्यावसायिक आवश्यकता के रूप में समझते हैं। दर्शकों में छात्रों के लिए - *यह कॉर्पोरेट कानूनों, प्रशासन प्रथाओं और समाजशास्त्र का ज्ञान है जो इसे प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अच्छी तरह से* ***शासित, विविध और समावेशी*** 3. कॉरपोरेट इंडिया इंडिया अपने लेनदारों के प्रति अपने सभी दायित्वों को पूरा करता है चाहे वे बैंक हों या बॉन्ड धारक हों, और चूक दुर्लभ हैं। साख और संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने से दुनिया भर में कॉर्पोरेट भारत का व्यवसाय भी जीता है, जो उन संगठनों और व्यक्तियों की सराहना करता है जो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं या उससे अधिक करते हैं। इसलिए, ग्राहक भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ व्यवसाय करने के लिए खुश हैं। दर्शकों में छात्रों के लिए - *यह अनुबंध कानून, कॉर्पोरेट कानून, दिवालियापन कोड, कर कानून, लेखा निहितार्थ और संरचना विशेषज्ञता का ज्ञान है जो वाणिज्यिक अनुबंधों, बैंक उधार या बांड जारी करने को आकार देता है। साख + संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का सम्मान* 4. प्रकाशित वित्तीय विवरणों में या निवेशकों को प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराई गई जानकारी में, कॉरपोरेट इंडिया ने उचित प्रकटीकरण और पारदर्शिता में एक स्वर्ण मानक निर्धारित किया है। ऐसे वित्तीय विवरण सत्य और निष्पक्ष होने के साथ-साथ सटीक, स्पष्ट, समझने योग्य होते हैं। दर्शकों में छात्रों के लिए - *यह समझना है कि वित्तीय विवरण कैसे तैयार किए जाते हैं - ये बड़े पैमाने पर कंपनी अधिनियम के तत्वावधान में बनाए जाते हैं, और वे लेनदेन और प्रकटीकरण से कैसे प्रभावित होते हैं या प्रभावित होते हैं, यह सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। खातों की और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में। ट्रू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वित्तीय और अन्य खुलासे* 5. भारतीय कॉर्पोरेट्स कॉर्पोरेट्स अपनी संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं, जिससे कि कोई विवाद होना दुर्लभ हैं । हालाँकि, जब विवाद उत्पन्न होते हैं, तो ऑनलाइन विवाद समाधान का उपयोग आदर्श होता है, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित, लागत प्रभावी समाधान होते हैं। ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता के संयोजन पर आधारित है। रोकथाम और मुद्दों के स्वत: समाधान के लिए तंत्र भी चालू हैं। व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) या व्यवसाय से ग्राहक (B2C) या वास्तव में कोई भी व्यवसाय या वाणिज्यिक या उपभोक्ता विवाद न्यायपालिका में नहीं जाते हैं। दर्शकों में छात्रों के लिए, यह हमारे निपटान में प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए ज्ञान और प्रशंसा है - जो ऑनलाइन विवाद समाधान या स्वचालित विवाद समाधान की अनुमति देता है, विवाद समाधान तटस्थों - मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। मध्यस्थ - साथ ही मैं आशा करता हूँ कि मध्यस्थता या ODR बार बन जाए। मेरा मानना ​​है कि आज दूसरा पैनल इनमें से कुछ पर ध्यान केंद्रित करेगा और मुझे उम्मीद है कि उस पैनल से बहुत कुछ हासिल होगा। ऑनलाइन विवाद समाधान और स्वचालित विवाद समाधान + विवाद निवारण के माध्यम से त्वरित विवाद समाधान 6. जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहल और न केवल कार्बन न्यूट्रल बल्कि कार्बन नेगेटिव बनने के परिणाम सामने आए हैं। कॉरपोरेट इंडिया ने हरित पहलों को अपनाया और अंतरिक्ष सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके निष्कर्षण उद्योगों या जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला या तेल के उपयोग से दूर हो गया। कॉर्पोरेट इंडिया ने ग्रीन डेट सिक्योरिटीज मानदंडों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिसने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में संक्रमण बांड, ब्लू बांड और येलो बांड की सुविधा भी प्रदान की। कई हिस्सों में वनीकरण हुआ है और वन्यजीव संरक्षण पशु प्रेमियों के लिए गर्व और खुशी का विषय है। भारत के जंगल अब शिकारियों को आकर्षित नहीं करते हैं, और प्रकृति और मानव आवास के बीच सामंजस्य है। दर्शकों में छात्रों के लिए, यह पर्यावरण कानूनों, तरीकों और हरित वित्त के साधनों का ज्ञान है, ग्रीनवाशिंग से बचना और जलवायु परिवर्तन पर की गई प्रतिबद्धताओं को समझना कानूनी ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पारिस्थितिक मित्रता ग्रीन जायंट बनाती है । 7. एक विज्ञान विज्ञान कथा प्रशंसक के रूप में - असिमोव एक व्यक्तिगत पसंदीदा है - यह उन महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करने के लिए जगह से बाहर नहीं होगा जो हमारे पास अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष यात्रा के लिए होनी चाहिए। मिशन मंगल या मंगल परियोजना ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे आगे होने के लिए प्रेरित किया, इन-स्पेस पहल - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) द्वारा सहायता प्राप्त - एक एकल-खिड़की, स्वतंत्र, नोडल एजेंसी के रूप में अंतरिक्ष विभाग के तहत जो 2020 में शुरू हुआ। मैं देखता हूं कि भारतीय कॉर्पोरेट अंतरिक्ष की खोज में सबसे आगे हैं, अंतरिक्ष यात्रा समाधान तैयार कर रहे हैं और वास्तव में अन्य ग्रहों और/या उनके चंद्रमाओं पर मानव बस्तियां बनाने में मदद कर रहे हैं। 1957 में स्पुतनिक के सोवियत प्रक्षेपण और 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के चंद्रमा पर पुरुषों के उतरने के साथ शुरू हुआ अंतरिक्ष युग को और गहरा आकार लेने की जरूरत है। दर्शकों में छात्रों के लिए, यह वायु और अंतरिक्ष कानून, चंद्रमा संधि और बाहरी अंतरिक्ष संधि का ज्ञान है जो कॉर्पोरेट कानूनों और धन उगाहने और वित्त और अन्वेषण और खनिज अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के साथ संयुक्त है जो हमें अच्छी स्थिति में खड़ा करेगा।   मैं मेटावर्स या एआई/एमएल पर नहीं रुकूंगा, जिसका प्रोफेसर पांडा ने विस्तार से उल्लेख किया है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इमर्सिव अनुभव और ऐसी प्रौद्योगिकियां विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दूरस्थ और अभी तक गहन शिक्षा और व्यापक अनुप्रयोग दोनों को सक्षम कर सकती हैं। उन लोगों के लिए जो चैटजीपीटी के चमत्कारों के बारे में उत्साहित हैं, यह ध्यान रखें कि जो कुछ हुआ है, यह केवल उसका एक पात्र है। मानवीय सरलता और प्रगति अतीत की सीखों से आगे बढ़ने के बारे में है, और यही लक्ष्य होना चाहिए।  यदि मैंने जो कुछ भी कहा वह काल्पनिक और समस्याओं व घोटालों से रहित लगता है जिसने कॉर्पोरेट क्षेत्र या वित्तीय बाजारों को पिछले कुछ वर्षों में या अब भी हिलाकर रख दिया है, तो इसे एक आशावादी दृष्टिकोण के रूप में सोचें, या विश्वास करने वाले के दृष्टिकोण के रूप में सोचें। हम सभी प्रत्येक चरण में खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करते हैं, और यदि ऐसा है, तो हम सभी और हमारे बच्चों और वंशजों से युक्त हमारे कॉर्पोरेट बुरे के बजाय अच्छा होने के फायदे देखते हैं।  अतीत के सुनहरे हिंद के रूप में जिसने भारत को दुनिया के लिए एक बेशकीमती गंतव्य बना दिया, और एक समय जब चीन के साथ भारत का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा था, तो यह 2050 में हो सकता है।  अब मैं विनियामक रुझानों की ओर मुड़ता हूं - एक बार फिर उसी के बारे में मेरे व्यक्तिगत विचार का प्रतिनिधित्व करता हूं - और जो सबसे सरल तरीके से व्यक्त किया जा सकता है वह इस प्रकार है:   1. भारत, भारतीय निवेशकों, भारत में निवेशकों और कॉर्पोरेट भारत को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, चाहे वह दबाव डालकर या अनिवार्य रूप से या ऐसे खुलासे की आवश्यकता हो जो सूचित निवेश या विनिवेश की ओर ले जाए। इसलिए, एक पूंजी बाजार नियामक के रूप में सेबी एक पूर्व-प्रतिष्ठित प्रकटीकरण आधारित नियामक व्यवस्था बना रहेगा। आरबीआई या आईआरडीएआई के मामले में, बैंकिंग और बीमा की प्रकृति को देखते हुए, उम्मीद की जा सकती है कि वे एक विवेकपूर्ण मानदंड संचालित, नियम आधारित नियामक व्यवस्था बने रहेंगे। 2. पूंजी बाजार में, प्रकटीकरण के मानकों की स्थापना, प्रकटीकरण में सहायता के लिए सामान्य वर्गीकरण और अलग-अलग जारीकर्ताओं और बिचौलियों द्वारा प्रकटीकरण की तुलना महत्वपूर्ण रहेगी। ये सूचित निवेशकों और सुरक्षित और अच्छे वातावरण में धन सृजन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बैंकिंग और बीमा में, जोखिमों की उचित पहचान और भंडार और बफ़र्स के निर्माण की आवश्यकता होती है यदि वे जोखिम बाहर निकलते हैं, और साथ ही, अंडरबैंक्ड या अनबैंक्ड या अंडरइंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड को संबोधित करने के लिए व्यवसाय को बढ़ाते हैं। संक्षेप में, संकट या आपदाओं या आपदाओं का सामना करने के लिए पूंजी और भंडार की पर्याप्तता सुनिश्चित करना और बीमा और बैंकिंग व्यवसाय को विवेकपूर्ण तरीके से करना। 3. पूंजी बाजार नियामक के लिए, विकासात्मक भूमिकाएं लेकर - उदाहरण के लिए REITs, InvITs या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के विकास और पोषण के साथ-साथ उसका समर्थन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र - बाजार, जारीकर्ताओं और निवेशकों को यथासंभव बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए। बैंकिंग विनियामक के लिए, भुगतान प्रणाली का पोषण करके - पहले से ही दुनिया में अग्रणी यूपीआई या आईएमपीएस, एनईएफटी या आरटीजीएस और फिनटेक, टेकफिन या बैंकटेक क्षेत्र के रूप में - वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने या वास्तव में वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में घर्षण को कम करने के लिए, सभी के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच रखने वाले नागरिक चाहे बचत करें या उधार लें या भुगतान करें या भुगतान प्राप्त करें। बीमा नियामक के लिए, कि नागरिक अपने जोखिमों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, बीमाकर्ताओं को जोखिम लेने के लिए भुगतान करके बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाता है - चाहे वह जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति का हो - और ऐसा आत्मविश्वास से जानते हुए करें कि बीमाकर्ता उस 3डी को लागू नहीं करेंगे जो बीमा क्षेत्र को बदनाम करता है - देरी, इनकार और बचाव। 4. बाजार की निगरानी और निगरानी करके किसी भी विसंगतियों या कदाचारों का पता लगाने के लिए या तो उचित प्रकटीकरण या व्यापारिक गतिविधियों में जो निवेशकों के विश्वास या खुद बाजार को कमजोर कर सकते हैं, और संक्षेप में, इसे निवेशकों के लिए एक उचित स्तर का खेल मैदान बनाए रखना। ओडीआर को अपनाने सहित निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूत तंत्र बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के भीतर, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल प्रक्रिया का चुनाव किया गया है। इन विभिन्न मॉडलों की सफलता भविष्य में अन्य नियामकों और नीति निर्माताओं द्वारा विकल्पों को सूचित करेगी। 5. पहचाने गए अपराधियों के खिलाफ प्रवर्तन उपाय करके और अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अपराधियों के खिलाफ उचित दंड या उपाय लागू करके, या सही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए जांच और मुकदमा चलाने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करना। न्यायिक समीक्षा, बाजार की गतिशीलता और वास्तविकताओं की उचित समझ के साथ बाजारों को साफ और सुरक्षित रहने को सुनिश्चित करने में बहुत दूर तक जाएगी।   मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं, और आपसे सूचित रहने और सीखते रहने - पढ़ने, सुनने या देखने - और भारत, दुनिया की चुनौतियों के लिए खुद को लागू करने और सभी के लिए शांति, समृद्धि और न्याय की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं।  धन्यवाद! |  | SPEECH  **Decoding the Key Sectors that can sustain the domestic economic recovery - REITs, InvITs, Data Centers and NBFCs[[1]](#footnote-1)**  It is a pleasure to be here this morning to deliver the keynote speech on REITs and InvITs which are being considered as key sectors that can sustain the domestic economic recovery.  The need for commercial real estate and for infrastructure assets of all hues and colors are overwhelming for any economy, and particularly for India as an emerging economy. Such assets when being built and after being built provide a huge impetus to other sectors of the economy as well. The superstructure of an economy is, after all, built on the infrastructure and real assets. The payback to the country and the economy can be manifold.  However, both real estate and infrastructure sector have been the bane for many a developer or sponsor.  It is fairly easy to understand the high risks carried:   * the risk of timely completion of such projects, * the cost escalations if timely completion has not occurred * Identifying and securing offtake or ready users or lessees for property * Co-mingling of cash flows of different projects and compromising disparate stakeholders * Challenges mounted by local citizenry or concerns from civil society organizations for reasons of environment or displacement without due rehabilitation, and so on that get mired in judicial process and contribute to time and cost overrun.   The developers themselves struggle to complete projects and if have multiple such projects, end up having to prioritize among them, while having no takeout for completed projects due to adverse publicity or capital markets not appearing favourable, and so on  These risks have often been transmitted onward to financiers whether be banks or bond holders. Even as the last credit cycle played out, banks either vacated the infrastructure lending or commercial real estate lending space or focused only on tier 1 names. In that sense the arrival of SEBI regulations for REITs and InvITs was quite timely. On lending side, it was complemented by creation of the infrastructure development funds companies.  REIT and InvIT immediately added to the available asset classes for investors to participate in, shorn of any other business activity or operations, and specifically providing exposure to and returns from commercial real estate in case of REITs, and infrastructure assets via the InvITs.  The design and concept of REITs and InvIT emphasizes that atleast 80% of assets held within such business trusts should be revenue generating (*when publicly issued and listed InvITs and all REITs - norms are slightly different for privately placed and listed InvITs*). Thus, the project completion risk or of off takers yet to be found in case of infrastructure assets, and similarly, of the real estate having lessees and tenants reduces the risks considerably for the investors.  For the developer, there’s a ready takeout of its equity stake, allowing recycling of the receipts toward other projects that are on the drawing board or which are work in progress. There is a continuing association on account of managing the operations via a project manager as well as the investment manager of the REIT/InvIT.  For investors, there’s a due opportunity to evaluate the assets and their income streams, and then to participate in owning them via the REIT/InvIT structure. That the developer continues to manage the operations and upkeep of the assets serves to provide a comfort of due expertise being available for the same. The payouts reflect the asset class underpinning the REIT and InvIT, whether in form of interest, dividend or other distributions made.  Hence it can be affirmed that REITs and InvITs have become a suitable structure for monetization of assets, and to briefly recapitulate:   * Given the phase of infrastructure in the country today, REITs and InvITs are expected to provide a suitable structure for financing/refinancing of real estate and infrastructure projects in the country. * REITs and InvITs, as an investment vehicle, may aid:   + providing of wider and long-term re-finance for existing real estate and infrastructure projects.   + freeing up of current developer capital for reinvestment into new real estate and infrastructure projects.   + refinancing/takeout of existing high cost debt with long-term low-cost capital and help banks free up/reduce loan exposure, and thereby create bank headroom for new funding requirements. * There are several real estate and infrastructure companies whose funds are locked up in completed/substantially completed real estate and infrastructure projects which can otherwise be used for furthering more real estate and infrastructure development in the country. REITs and InvITs can be an enabling vehicle for refinancing such assets as well as creating an investment option which may otherwise not be possible for investors desirous of such exposure. * REITs and InvITs are allowed for adding projects in future in the same vehicle so that investors can benefit from diversification as well as growth in their portfolio. REITs and InvITs may help in attracting international finance into the Indian real estate and infrastructure sectors. REITs and InvITs will enable the investors to hold a diversified portfolio of real estate and infrastructure assets. * REITs and InvITs are also expected to bring higher standards of governance into infrastructure development and management and distribution of income from assets so as to attract investor interest   Since REITs and InvITs are allowed to leverage themselves directly or thru the HoldCos or SPVs set up, with due approval of unit holders when such leverage is of particular level, while being capped at a certain level, allows due fundraising and utilization for new project development or for operations and maintenance. Given the cash flow from income generating assets backing the fund raising, and requirement of rating, the debt so issued is also attractive to fixed income investors.  From a regulatory perspective, the design and structure of REITs and InvITs have served the key objectives of making available new asset class for investors to participate in, with due knowledge and disclosures being made at the initial and on a continuous basis. Equally, measures over the years have also been to enable more and more investors to participate in REITs and InvITs, reflected in reduction in the initial subscription being lowered to Rs 10,000/- and trading lot being a single unit.  So what is next for REITs and InvITs?   1. Even as retail participation is enabled and also taking place, it is the right juncture for the REITs and for InvITs to coalesce into an association. Just as AMFI - Association of Mutual Fund Industry - plays a critical role in evangelizing mutual funds as an asset class - think ‘Mutual Fund Sahi Hai’ campaign, one can envisage association of REITs saying ‘REITs Right hai!’. Rather than be the copywriter (and getting judged on those skills), what i would note is that individually for any REIT or InvIT promoting the entire asset class may be difficult, whereas an association may be better placed to do so. Presenting industry views or being conveyed regulatory guidance via an association also becomes more conducive. 2. Given the close nexus with the developer sponsor, whether on account of the initial assets acquired or after, and that such assets being maintained and managed by developer or its affiliates, focus on ensuring that all the commercial relationships are on an arms’ length basis and ensuring that no related party transactions are adverse to the REIT or InvIT and accordingly to the unit holders, will be a key element to maintain and enhance investor confidence in REITs and InvITs. For rating agencies as much as independent directors, valuers and auditors, these interlinkages being on fair terms should form part of the assessment and decision making. 3. Leverage- I mentioned a bit earlier about the ability of REITs and InvITs to borrow from banks or by issue of bonds - which is serviced from the cash flow from the assets. This is a key way that the exiting REITs and InvITs will scale and be able to provide balanced returns. Given that much of such leverage is either contracted even prior to constituting of the REITs or InvITs, and/or is of long term nature (some of the repayments stretch to 15-20 year tenures), there is a need to look at how unitholder interests are best protected and if there’s a way to ensure due alignment of interests of the sponsors and unit holders in this context. 4. On a separate note, we are keen to explore and give shape to creation of mortgage REITs - which can serve to bring focus on residential mortgage backed securities and commercial mortgage backed securities - RMBS and CMBS - or essentially, making available permanent pool of capital for securitization of such mortgages, and making them available to investors. We hope to issue a consultation paper soon and will evaluate the feedback on making the same operational. 5. It is also understood that commercial real estate of certain size and form are being packaged and distributed by certain fractional real estate investment platforms. These are unregulated products, outside regulatory perimeter and could be rife with conflicts, lack of exit options for investors, and have embedded legal risks. A closer look is warranted on such fractional real estate investment platforms and in safeguarding investor interests. If it is to be brought within regulatory perimeter, the current REIT regulations will provide a good framework that could be, with some changes, be made applicable to such fractional real estate investment platforms. We will consider issuing a consultation paper and evaluate the feedback on addressing the same. 6. Given also the emphasis on urban infrastructure and role of municipal corporations - with this drawing mention in this year’s budget speech by the FM - one element we are considering is enabling creation of InvITs which can acquire urban infrastructure assets from municipal corporations and operate them, akin to how other public private partnerships have been undertaken or via a concession agreement with the municipal corporation. Apart from bolstering municipal finances and releasing revenue generating assets for public investments, it offers municipalities an opportunity to receive funds for further urban infrastructure development. 7. The recent tax proposal has also drawn industry feedback that accepts the case for taxation, albeit as and under the heading of capital gains rather than as income from other sources as proposed. While it is for MoF to consider this, please do note that the underlying flows received by the REIT or InvIT have the match the onward distribution to the unitholders. So moneys received as interest necessarily is paid onward as interest, and dividend received paid onward as dividend. Such matched flows is what makes REIT and InvIT a pass through entity, which must not be lost sight of. 8. Focus on governance regarding REITs and InvITs will not be limited to looking only at the IM - investment manager. Good governance is expected in the HoldCos/SPVs and in the project manager or manager as well. Due oversight by independent directors of IM must extend to these entities as must internal controls and audit assurance process. Being mindful of related party transactions with sponsor and sponsor controlled entities, and ensuring these are at arms’ length and not exploitative or adverse or unfair lies on the management and their supervisors the Board including independent directors. This leads to due protection of unitholders, which should remain the matter of utmost priority to the Board at the IM. 9. Investors have flocked to this asset class, and many of them are global investors including sovereign wealth funds, overseas pension funds and other long term investors. The diligence and scrutiny and extensive involvement of such investors with the REITs and InvITs inspires confidence, which such investors should be cognizant about. Such investors should abide by the stewardship code that has been established for institutional investors. Many more investors will follow this smart money and shouldn’t be left smarting from inaction or obliviousness to situations demanding unitholder intervention or self-dealing that puts them ahead of other unitholders. 10. Finally, many regulated entities support and service REITs and InvITs, including Debenture Trustee constituted as the trustees, Credit Rating Agencies for rating of debt securities issued by REITs and InvITs, the Depositories where the units are held in dematerialized form and the Stock Exchanges where the units are listed. Each such intermediary should render professional, independent and above reproach service, while performing the role that their nature of service requires. This serves as a check and balance upon the REITs and InvITs and protects the interests of the unitholders.   With this I turn back the discussion to decoding the key sectors that can sustain domestic economic recovery, and commend the sessions in doing so with a view to ensure regulatory and investor expectations are met in the short, medium and long term.  Thank you!  **Positioning of Corporate India in 2050 and the Regulatory Trends**  Pramod Rao  G’morning to all of you: it is a pleasure and a privilege to be here at Konfluence 2023 - *Mega Corporate Conclave* and speaking on *the Positioning of Corporate India in 2050 and the Regulatory Trends*.  I also must acknowledge my gratitude to Professor NL Mitra, in the audience today, who was my professor at NLS Bangalore and later it’s Vice Chancellor, who taught us banking, insurance, and law, accounting and financial management, among the key subjects that dominate my professional life, and to have an outlook in life to learn and to contribute to the development of the law in the Indian financial services sector.  I speak in my personal capacity and being an ardent observer of the Indian corporate sector, from, if memory serves me right, 2nd of law school in the five year law program at National Law School Bangalore. I read cover to cover the Economic Times that the Law School subscribed to and found I was the only one reading at least in the first couple of years. That reading habit - whether of print or on social media - I would encourage all of you to adopt. Given the millennials who are in the audience, viewing - whether on YouTube or OTT or listening to podcasts or audiobooks works just as well.  What such observations, reading, listening and viewing have led me to project into 2050, and as if we have been teleported to 2050, are as follows:   1. Corporate India is well geared to international and domestic markets. It understands what it takes to succeed, in being competitive and being respectful of all stakeholders. Such stakeholders include its own employees, outsourced staff, vendors, suppliers and service providers, as well as its customers, regulators and the governments of the countries that the Indian corporate sector have operations in. *For the students in the audience, it’s the Knowledge and understanding of stakeholders and markets - what motivations drive the stakeholders and what constitutes fairness in dealing with such stakeholders.* ***Fair dealings with.*** 2. Corporate India is well governed by its Board, which is diverse and represents the markets it operates in. Diversity is both of gender and also of perspectives that come from the domestic and international markets, and in being able to co-opt different strands that comprise the society. Such diversity which began as an imposition by the capital market regulator in requiring women directors and later women independent directors, no longer is done due to regulatory imposition but because the Corporates understand it as a business necessity to be reflective of the society it is part of and operates in. *For the students in the audience, it is the Knowledge of corporate laws, governance practices and sociology that can help achieve this.* ***Well-governed, Diverse & Inclusive.*** 3. Corporate India performs all its obligations to its creditors whether be banks or bond holders, and defaults are rare. Creditworthiness and honoring contractual commitments has also won Corporate India business from around the world, which appreciates organizations and individuals who live upto or exceed their commitments. Hence, customers and clients are pleased to deal with the Indian corporate sector. *For the students in the audience, it is the Knowledge of contract law, corporate law, bankruptcy code, tax laws, accounting implications and structuring expertise that shape the commercial contracts, bank borrowing or bond issuances*. ***Creditworthy*** + ***Honoring contractual commitments*** 4. Whether in the financial statements that are published or in the information made available to the stock exchanges for dissemination to investors, Corporate India has set a gold standard in due disclosures and transparency. Such financial statements are accurate, clear, understandable while being true and fair. *For the students in the audience, it is the Understanding of how financial statements are drawn up - these are largely created under the aegis of the Companies Act, and how they are impacted by or impact transactions and disclosures is key to ensuring true and fair view of accounts and towards ensuring transparency*. ***True*** ***Fair & Transparent financial and other disclosures*** 5. Disputes are rare, given Indian corporates meeting their contractual commitments. However, when disputes do arise, usage of Online dispute resolution is the norm, which results in speedy, cost effective resolutions. Online dispute resolution system is based on a combination of mediation, conciliation and arbitration. Mechanisms for prevention and automatic addressing of issues are also operational. Business to business (B2B) or Business to Customer (B2C) or indeed any business or commercial or consumer disputes don’t go to the judiciary. *For the students in the audience, it is the knowledge of and appreciation for alternative dispute resolution, with use of technology at our disposal - which permits online dispute resolution or automated dispute resolution will provide a fresh impetus to dispute resolution neutrals - mediators, conciliators and arbitrators - as well as what I hope becomes the arbitration or the ODR bar. I believe the second panel today will focus on some of these and I hope to have many takeaways from that panel.* ***Prompt Dispute Resolution via Online dispute resolution and automated dispute resolution + Dispute prevention*** 6. Initiatives to combat climate change and becoming not just carbon neutral but carbon negative have borne fruit. Corporate India embraced the green initiatives and moved away from extractive industries or usage of fossil fuels such as coal or oil by harnessing renewable energy sources including space solar power, wind power and renewable oceanic energy. Corporate India effectively utilized the Green Debt Securities norms which also facilitated Transition Bonds, Blue Bonds and Yellow Bonds in achieving these objectives. Afforestation has occurred in many parts and wildlife conservation is a matter of pride and joy for animal lovers. Jungles of India no longer attract hunters, and there is harmony of nature and human habitation. *For the students in the audience, it is the knowledge of environmental laws, modes and means of green finance, avoiding greenwashing and understanding the commitments made on climate change will be critical portions of legal knowledge*. ***Ecological Friendliness creates Green Giants.*** 7. As a sci-fi fan - Asimov is a personal favorite - it wouldn’t be out of place to talk about ambitions that we should have for space exploration and space travel. The Mission Mangal or Mars project gave rise to India being at the forefront of space exploration, aided by the In-SPACe initiative - the Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) - as a single- window, independent, nodal agency under Department of Space that began in 2020. I see Indian corporates being at the forefront of exploring space, creating space travel solutions and indeed helping create human settlements on other planets and/or their moons. The space age which began with the Soviet launch of Sputnik in 1957 and the USA landing Men on the Moon in 1969 needs to take further and deeper shape. *For the students in the audience, it is the knowledge of Air and Space law, the Moon Treaty and the Outer Space Treaty combined with corporate laws and laws governing fundraising and finance and exploration and mineral rights that will stand us in good stead*   I’ll not dwell on metaverse or AI/ML which Prof Panda referred to elaborately. Suffice it to say that immersive experiences and such technologies can enable both remote and yet deep learning and wide application across different disciplines and fields. For those who are enthusiastic about the wonders of ChatGPT, do keep in mind it is only a receptacle of what has happened. Human ingenuity and progress is about advancing beyond the learnings of the past, and that should be the goal.  If all of what I said sounds fanciful or devoid of issues, scams or scandals that have rocked the corporate sector or the financial markets over the years gone by or even now, think of it as an optimist’s outlook, or a view of one who believes. We all strive to be a better version of ourselves at each stage, and if that be so, then our corporates comprising of all of us and our children and descendants see the benefits of being good rather than bad.  Just as the Golden Hind of the past that made India a prized destination for the world, and a time when India along with China accounted for over 40% of world’s GDP, so it can be in 2050.  I now turn to the regulatory trends - representing once more my personal take of the same - and which in the most simplistic manner that one can convey is as follows:   1. To enable India, Indian investors, Investors in India and Corporate India to achieve their objectives, whether by nudging or mandating or by requiring disclosures that leads to informed investments or divestments. Hence, SEBI as a capital markets regulator will remain a pre-eminent disclosure based regulatory regime. In case of RBI or IRDAI, given the nature of banking and insurance, one can expect that they would remain a prudential norms driven, rule based regulatory regime. 2. In capital markets, setting standards of disclosure, common taxonomies to aid disclosure and comparison of disclosure by disparate issuers and intermediaries will remain a key. These will be key to informed investors and wealth creation in a safe and sound environment. In banking and insurance, it is requiring due recognition of risks and creation of reserves and buffers if those risks play out, and at the same time, growing the business to address the underbanked or unbanked or underinsured or uninsured. In short, ensuring adequacy of capital and reserves to withstand crisis or calamities or catastrophes, and doing insurance and banking business prudently. 3. For capital markets regulator, by undertaking developmental roles - *for instance in developing and nurturing REITs, InvITs or Municipal Bonds as well as the ecosystem supporting the same* - to overall grow the market, issuers and investors in as sound a manner as possible. For banking regulator, by nurturing the payment systems - already world leading in form of UPI or IMPS, NEFT or RTGS and the FinTech, TechFin or BankTech sector - to ease the friction in availing of financial services or indeed utilizing the financial services, with all citizenry having access to banking facilities whether to save or borrow or to pay or receive payments. For insurance regulator, that citizenry can have their risks are better managed by paying insurers to take on the risk - be it of life, health or property - and do so confidently knowing that insurers will not apply the 3D that brings disrepute to the insurance sector - delay, deny and defend. 4. By monitoring and surveilling the market to detect any anomalies or malpractices either in due disclosures or in trading activities that could undermine investor confidence or the market itself, and in short, keeping it a fair level playing field for investors. Creating robust mechanisms to address investor grievances including adoption of ODR will remain key. Within the banking and insurance sector, the choice has been of having an ombudsman process to redress customer grievances. Success of these different models will inform choices in future by other regulators and policymakers. 5. By taking enforcement measures against malefactors identified and imposing appropriate penalties or measures against such malefactors when within its jurisdiction, or instituting appropriate action for rightful law enforcement agencies to investigate & prosecute. Judicial review, with due understanding of market dynamics and realities will go a far way in ensuring the markets stay clean and secure.   I end with these words, and to urge you to stay informed and to keep learning - by reading, listening or watching - and applying yourself to the challenges of India, the world and in coming together in working towards peace, prosperity and justice for all.  Thank you! |

पूँजी बाजार - एक समीक्षा

**CAPITAL MARKET REVIEW**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. कंपनियों द्वारा जुटाया गया पैसा :  * **फरवरी 202**3 **के दौरान, इक्विटी निर्गमों (इश्यू) के जरिए** 21,374 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई, जबकि जनवरी 202**3 **के दौरान** 1,951 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई थी ।** * **फरवरी 202**3 **में,** 7 **आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाए गए, जिनके जरिए कुल** 85 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई । इन कुल आईपीओ में से, सभी** 7 **निर्गम (इश्यू) एसएमई / शुरूआती कंपनियों (स्टार्टअप) द्वारा लाए गए थे, जिनके जरिए** 85 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई (सारणी 1) ।** * 485 **करोड़ रुपये की रकम तो** 10 **साधिकार निर्गमों (राइट्स इश्यू) के जरिए जुटाई गई ।** * **फरवरी 202**3 **के दौरान, अधिमानी आबंटन** (**प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) के जरिए** 20,804 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई, जबकि जनवरी 202**3 **में** 829 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई थी । फरवरी 202**3 **के दौरान, क्यूआईपी से कोई रकम नहीं जुटाई गई ।** * **फरवरी 202**3 **के दौरान, ऋण** (**डैट) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के जरिए** 188 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई, जबकि जनवरी 202**3 **के दौरान** 1863 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई थी । फरवरी 202**3 **के दौरान, ऋण (डैट) के प्राइवेट प्ले**समें**ट के जरिए** 93,859 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई, जबकि जनवरी 202**3 **के दौरान** 65,666 **करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई थी ।** | 1. **Trends in Resource Mobilisation by Corporates**  * Resource mobilised through equity issuances was ₹ 21,374 crore during February 2023, compared to ₹ 1,951 crore during January 2023. * There were 7 IPOs in February 2023, through which a total of ₹ 85 crore was mobilized. Of the total IPOs, all 7 issues were SME/start-up listings which mobilised ₹ 85 crore (Table 1). * Funds amounting to ₹485 crore were raised through 10 rights issues. * Amount raised through preferential allotment during February 2023 was ₹ 20,804 crore, compared to ₹ 829 crore raised in January 2023. There were no QIPs during February 2023. * ₹ 188 crore was mobilised through public issue of debt during February 2023, compared to the ₹1863 crore raised during January 2023. Private placement of debt raised ₹ 93,859 crore during February 2023, compared to ₹65,666 crore during January 2023. |

सारणी 1: कंपनियों द्वारा जुटाया गया पैसा (₹ करोड़ में)

**Table 1: Fund Mobilisation by Corporates (₹ crore)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **विवरण / Particulars** | जनवरी **/ Jan - 23** | **फरवरी / Feb -** 2**3** |
| ***I. इक्विटी निर्गम (इश्यू)***  ***Equity Issues*** | 1,951 | 21,374 |
| क. आईपीओ  a. IPOs (i+ii) | 478 | 85 |
| *i. मुख्य-बोर्ड*  *Main Board* | 323 | 0 |
| *ii. एसएमई प्लेटफॉर्म*  *SME Platform* | 155 | 85 |
| ख. एफपीओ  b. FPOs | 0 | 0 |
| ग. इक्विटी साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)  c. Equity Rights Issues | 644 | 485 |
| घ. क्यूआईपी / आईपीपी  d. QIPs / IPPs | 0 | 0 |
| ङ. अधिमानी आबंटन (प्रेफ्रेंशियल अलॉटमेंट)  e. Preferential Allotments | 829 | 20,804 |
| ***II. ऋण निर्गम (डैट इश्यू)***  ***Debt Issues*** | 67,529 | 94,046 |
| क. ऋण सार्वजनिक निर्गम (डैट पब्लिक इश्यू)  a. Debt Public Issues | 1,863 | 188 |
| ख. ऋण (डैट) का प्राइवेट प्लेसमेंट  b. Private Placement of Debt | 65,666 | 93,859 |
| **जुटाया गया कुल पैसा**  **Total Funds Mobilised (I+II)** | 69,480 | 1,15,421 |

**स्रोत: सेबी, बीएसई, एनएसई और एमएसईआई**

**Source:** SEBI, BSE, NSE and MSEI

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **द्वितीयक** बाजार **(सेकेंडरी मार्केट) के रुख**  * **फरवरी 202**3 के दौरान, निफ्टी और सेंसेक्स में पिछले महीने की तुलना में क्रमशः 2.0 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत तक की गिरावट आई । इसके साथ-साथ, **जनवरी 202**3 के आँकड़ों की तुलना में, बीएसई और एनएसई के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) में भी 4.6 और 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई । **फरवरी 202**3 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 का पी/ई अनुपात क्रमशः 22.8 और 20.9 रहा । | 1. **Trends in the Secondary Market**  * During February 2023, Nifty and Sensex fell by 2.0 per cent and 1.0 per cent respectively over the previous month. Reflecting the downtrend, market capitalization at BSE and NSE recorded a fall of 4.6 per cent and 4.5 per cent respectively, over the end of January 2023. The average P/E ratios of S&P BSE Sensex and Nifty 50 were 22.8 and 20.9 respectively, for the month of February 2023. |

सारणी 2: भारत का पूँजी बाजार – एक नज़र में

**Table 2: Snapshot of the Indian Capital Market**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **विवरण**  **Description** | **जनवरी / Jan - 23** | **फरवरी / Feb -** 2**3** | **माह-दर-माह परिवर्तन (% में)**  **M-o-M variation (%)** |
| **इक्विटी बाजार सूचकांक / Equity Market indices** | | | |
| निफ्टी 50 / Nifty 50 | 17,662 | 17,304 | -2.0 |
| सेंसेक्स / Sensex | 59,550 | 58,962 | -1.0 |
| निफ्टी मिडकैप 50 / Nifty Midcap 50 | 8,638 | 8,457 | -2.1 |
| निफ्टी स्मॉलकैप 100 / Nifty Smallcap 100 | 9,502 | 9,156 | -3.6 |
| बीएसई मिडकैप / BSE Midcap | 24,643 | 24,158 | -2.0 |
| बीएसई स्मॉलकैप / BSE Smallcap | 28,206 | 27,341 | -3.1 |
| **बाजार पूँजीकरण / Market Capitalisation (₹ करोड़ में / ₹ crore)** | | | |
| बीएसई / BSE | 2,70,23,160 | 2,57,72,501 | -4.6 |
| एनएसई / NSE | 2,68,02,351 | 2,55,83,222 | -4.5 |
| **पी/ई अनुपात (मासिक औसत)**  **P/E Ratio (monthly average)** | | | |
| सेंसेक्स / Sensex | 23.3 | 22.8 | -1.9 |
| निफ्टी 50 / Nifty 50 | 21.5 | 20.9 | -2.7 |
| **सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या**  **No of Listed Companies** | | | |
| बीएसई / BSE | 5,444 | 5,422 | -0.4 |
| एनएसई / NSE | 2,179 | 2,190 | 0.5 |
| **इक्विटी खंड (सेगमेंट) में सकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) (₹ करोड़ में)**  **Gross Turnover in Equity Segment (₹ crore)** | | | |
| बीएसई / BSE | 68,103 | 71,059 | 4.3 |
| एनएसई / NSE | 10,20,626 | 10,04,997 | -1.5 |
| **इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) (₹ करोड़ में)**  **Gross Turnover in Equity Derivatives Segment (₹ crore)** | | | |
| बीएसई / BSE | 1,99,741 | 1,40,346 | -29.7 |
| एनएसई / NSE | 42,45,23,059 | 41,63,48,524 | -1.9 |
| **करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में सकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) (₹ करोड़ में)**  **Gross Turnover in Currency Derivatives Segment (₹ crore)** | | | |
| बीएसई / BSE | 5,25,803 | 3,09,705 | -41.1 |
| एनएसई / NSE | 41,05,930 | 31,82,425 | -22.5 |
| एमएसईआई / MSEI | 24,043 | 25,118 | 4.5 |
| **इंटरेस्ट रेट (ब्याज दर) डेरिवेटिव सेगमेंट में सकल व्यापारावर्त (₹ करोड़ में)**  **Gross Turnover in Interest Rate Derivatives Segment (₹ crore)** | | | |
| बीएसई / BSE | 1,225 | 2,691 | 119.6 |
| एनएसई / NSE | 2,033 | 2,680 | 31.8 |

स्रोत: **बीएसई, एनएसई और एमएसईआई**

**Source:** BSE, NSE and MSEI

**आकृति 1 : एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हुए उतार-चढ़ाव**

**Figure 1: Movement of S&P BSE Sensex and Nifty 50**

**स्रोत: बीएसई और एनएसई**

**Source:** BSE and NSE

|  |  |
| --- | --- |
| * **फरवरी 202**3 **के दौरान, एक्सचेंजों** में ट्रेडिंग में बढ़त आई, और पिछले महीने की तुलना में इक्विटी नकदी खंड (कैश सेगमेंट) के औसत दैनिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) में 3.8 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज हुई । **फरवरी 202**3 के दौरान, एक्सचेंजों के नकदी खंड (कैश सेगमेंट) के सकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) में 1.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई । | * During February 2023, trading activity has increased at exchanges with average daily turnover at equity cash segment up by 3.8 per cent over the previous month. However, gross turnover in the cash segment at exchanges fell by 1.2 per cent in February 2023**.** |

**आकृति 2 : एक्सचेंजों के इक्विटी नकदी खंड (कैश सेगमेंट) में औसत दैनिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख (₹ करोड़ में)**

**Figure 2: Trends in Average Daily Turnover at Equity Cash Segment of Exchanges (₹ crore)**

**स्रोत: बीएसई और एनएसई**

**Source:** BSE and NSE

|  |  |
| --- | --- |
| * चयनित क्षेत्रीय सूचकांकों में, फरवरी 2023 के दौरान, केवल दो सूचकांकों ने मामूली सकारात्मक रिटर्न दिखाया, अर्थात निफ्टी एफएमसीजी (1.1 प्रतिशत पर) और बीएसई कैपिटल गुड्स (0.2 प्रतिशत पर)। अन्य सूचकांकों की तुलना में इन सूचकांकों की अस्थिरता सबसे कम थी। बीएसई पावर (-15.6 प्रतिशत पर) का रिटर्न सबसे कम था, उसके बाद बीएसई मेटल (-10.2 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू (-8.7 प्रतिशत), बीएसई ऑयल (-8.6 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (-8.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। प्रतिशत)। फरवरी 2023 के लिए इन चुनिंदा सूचकांकों के औसत दैनिक उतार-चढ़ाव और मासिक रिटर्न को चित्र 3 में दिखाया गया है। | * Among the selected sectoral indices, during February 2023, only two indices showed marginal positive returns, viz., Nifty FMCG (at 1.1 per cent) and BSE Capital Goods (at 0.2 per cent). Volatility of these indices was amongst the lowest compared to other indices. BSE Power (at -15.6 per cent) had lowest returns followed by BSE Metal (at -10.2 per cent), Nifty PSU (at -8.7 per cent), BSE Oil (at -8.6 per cent) and Nifty Energy (at -8.6 per cent). The average daily volatility and monthly returns of these select indices for February 2023 are illustrated in Figure 3. |

आकृति 3 : फरवरी 2023 के दौरान बीएसई और एनएसई के क्षेत्रों (सेक्टर) के सूचकांकों (इंडेक्स) के रुख (प्रतिशत में**)**

**Figure 3: Trends of BSE and NSE Sectoral Indices during January 2023 (percent)**

**स्रोत: रिफिनिटिव**

**Source:** Refinitiv

|  |  |
| --- | --- |
| **III.** निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) के यहाँ खोले गए खातों के रुख   * फरवरी **202**3 **में, एनएसडीएल में 4 लाख और डीमैट खाते खोले गए, जबकि सीडीएसएल में 1**7 **लाख और डीमैट खाते खोले गए ।** फरवरी **202**3 **के अंत तक की स्थिति के अनुसार, एनएसडीएल में 3.**12 **करोड़ डीमैट खाते थे और सीडीएसएल में** 8.14 **करोड़ ।** | **III. Trends in Depository Accounts**   * NSDL added 4 lakh demat accounts while CDSL added 17 lakh demat accounts in February 2023. At the end of February 2023, 3.12 crore demat accounts were registered with NSDL and 8.14 crore with CDSL. |

आकृति 4 : खुलवाए गए नए डीमैट खाते (महीने के अनुसार) [लाख में]

**Figure 4: Monthly New Demat Accounts Added (in lakh)**

**स्रोत: एनएसडीएल, सीडीएसएल**

**Source:** NSDL, CDSL

|  |  |
| --- | --- |
| **IV. डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट के रुख**   1. **इक्विटी डेरिवेटिव**   **बीएसई**  फरवरी **202**3के दौरान, बीएसई के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का आनुमानिक व्यापारावर्त (नोशनल टर्नओवर) 29.7 प्रतिशत तक घटकर 1.4 लाख करोड़ रुपये रह गया ।  **एनएसई**  फरवरी **202**3के दौरान, एनएसई के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का मासिक आनुमानिक व्यापारावर्त (नोशनल टर्नओवर) 1.9 प्रतिशत तक घटकर 4,163 लाख करोड़ रुपये हो गया । | 1. **Trends in Derivatives Segment** 2. **Equity Derivatives**   **BSE**  During February 2023, the notional turnover of the equity derivatives segment at BSE fell significantly by 29.7 percent to ₹1.4 lakh crore.  **NSE**  The monthly notional turnover in the equity derivatives segment at NSE fell by 1.9 per cent to ₹4,163 lakh crore during February 2023. |

**आकृति 5 : बीएसई और एनएसई में औसत दैनिक आनुमानिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख (₹ करोड़ में)**

**Figure 5: Trends of Average Daily Notional Turnover at BSE and NSE (₹ crore)**

**Note:** ADNT implies Average Daily Notional Turnover

**स्रोत: बीएसई और एनएसई**

**Source:** BSE and NSE

सारणी 3: इक्विटी डेरिवेटिव बाजार के रुख

**Table 3: Trends in Equity Derivatives Market**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण /**  **Description** | **एनएसई / NSE** | | | **बीएसई / BSE** | | |
| **जनवरी / Jan-23** |  | **एक महीने में बदलाव (प्रतिशत में) / Percentage Change Over Month** | **जनवरी / Jan-23** |  | **एक महीने में बदलाव (प्रतिशत में) / Percentage Change Over Month** |
| **क. व्यापारावर्त (₹ करोड़ में)**  **A. Turnover (₹crore)** | | | | | | |
| **(i) इंडेक्स फ्यूचर्स Index Futures** | 7,90,757 | 7,76,179 | -1.8 | 5 | 4 | -22.6 |
| **(ii) इंडेक्स पर ऑप्शन्स**  **Options on Index** |  |  |  |  |  |  |
| ***पुट***  ***Put*** | 20,24,46,725 | 19,89,12,401 | -1.7 | 19,094 | 23,083 | 20.9 |
| ***कॉल***  ***Call*** | 21,48,24,310 | 21,00,62,938 | -2.2 | 1,80,642 | 1,17,259 | -35.1 |
| **(iii) स्टॉक फ्यूचर्स Stock Futures** | 15,94,094 | 15,18,191 | -4.8 | 0 | 0 | - |
| **(iv) स्टॉक पर ऑप्शन्स**  **Options on Stock** |  |  |  |  |  |  |
| ***पुट***  ***Put*** | 16,03,849 | 16,78,208 | 4.6 | 0 | 0 | - |
| ***कॉल***  ***Call*** | 32,63,323 | 34,00,606 | 4.2 | 0 | 0 | - |
| **कुल / Total** | **42,45,23,059** | **41,63,48,524** | **-1.9** | **1,99,741** | **1,40,346** | **-29.7** |
| **ख. कॉण्ट्रैक्ट की संख्या**  **B. No. of Contracts** | | | | | | |
| **(i) इंडेक्स फ्यूचर्स Index Futures** | 81,55,396 | 81,16,335 | -0.5 | 51 | 40 | -21.6 |
| **(ii) इंडेक्स पर ऑप्शन्स**  **Options on Index** |  |  |  |  |  |  |
| ***पुट***  ***Put*** | 2,14,24,80,179 | 2,16,42,22,604 | 1.0 | 2,09,626 | 2,57,823 | 23.0 |
| ***कॉल***  ***Call*** | 2,23,18,92,337 | 2,23,23,75,454 | 0.0 | 17,69,526 | 11,85,603 | -33.0 |
| **(iii) स्टॉक फ्यूचर्स Stock Futures** | 2,30,04,032 | 2,35,51,012 | 2.4 | 0 | 0 | - |
| **(iv) स्टॉक पर ऑप्शन्स**  **Options on Stock** |  |  |  |  |  |  |
| ***पुट***  ***Put*** | 2,30,60,962 | 2,73,52,119 | 18.6 | 0 | 0 | - |
| ***कॉल***  ***Call*** | 4,40,67,890 | 4,93,79,951 | 12.1 | 0 | 0 | - |
| **कुल / Total** | **4,47,26,60,796** | **4,50,49,97,475** | **0.7** | **19,79,203** | **14,43,466** | **-27.1** |

स्रोत: **बीएसई और एनएसई**

**Source:** BSE and NSE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **करेंसी (मुद्रा) डेरिवेटिव**  * फरवरी **202**3 **के दौरान, भारत में करेंसी डेरिवेटिव का मासिक आनुमानिक व्यापारावर्त (नोशनल टर्नओवर)** **[एनएसई, बीएसई और एमएसईआई का मिलाकर]** 24.5 **प्रतिशत तक** घटकर35.2 **लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि** जनवरी2023 **में यह** 46.6 **लाख करोड़ रुपये था।** | 1. **Currency Derivatives**  * The monthly notional turnover of currency derivatives in India (NSE, BSE, and MSEI together) fell by 24.5 percent to ₹35.2 lakh crore in February 2023 as compared to ₹46.6 lakh crore in January 2023. |

आकृति 6: एनएसई, एमएसईआई और बीएसई में करेंसी (मुद्रा) डेरिवेटिव के रुख (₹ करोड़ में)

**Figure 6: Trends of Currency Derivatives at NSE, MSEI, and BSE (₹ crore)**

**स्रोत: बीएसई, एनएसई और एमएसईआई**

**Source:** BSE, NSE and MSEI

|  |  |
| --- | --- |
| 1. इंटरेस्ट रेट (ब्याज दर) डेरिवेटिव  * फरवरी **202**3 **में, बीएसई के इंटरेस्ट रेट** डेरिवेटिव सेगमेंट **में, मासिक आनुमानिक व्यापारावर्त (नोशनल टर्नओवर) बढ़कर** 2,691 **करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले महीने यह** 1,225 **करोड़ रुपये था । इसी अवधि के दौरान, एनएसई में यह 2,**033 **करोड़ रुपये से बढ़कर 2,**680 **करोड़ रुपये हो गया ।** | 1. **Interest Rate Derivatives**  * In the interest rate derivatives segment at BSE, the monthly notional turnover rose to ₹2,691 crore in February, 2023 from ₹1,225 crore in the previous month. At NSE it rose to ₹2,680 crore from ₹2,033 crore during the same period. |

**आकृति 7 : एनएसई और बीएसई के इंटरेस्ट रेट (ब्याज दर) डेरिवेटिव के रुख (₹ करोड़ में)**

**Figure 7: Trends of Interest Rate Derivatives at NSE and BSE (₹ crore)**

**स्रोत: बीएसई और एनएसई**

**Source:** BSE and NSE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. कंपनी ऋण बाजार (कारपोरेट डैट मार्केट)  * फरवरी **202**3 **के दौरान, एक्सचेंजों में 1**7,175 **कंपनी** (**कारपोरेट**) **बॉण्ड खंडों का निपटान (सेटलमेंट) किया गया, जिनका मूल्य** 1,16,831 **करोड़ रुपये का था । इनमें सूचीबद्ध (लिस्टिड) और असूचीगत (अनलिस्टिड)** **कंपनी (कारपोरेट) बॉण्ड दोनों के ओटीसी ट्रेड और आरएफक्यू ट्रेड शामिल हैं ।** | 1. **Corporate Debt Market**  * During February 2023, 17,175 trades with value of ₹1,16,831 crore were settled across the corporate bond segments at exchanges. This includes OTC trades and RFQ trades of both listed and unlisted corporate bonds. |

**आकृति 8 : कारपोरेट बॉण्ड के सूचित किए गए व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख (₹ करोड़ में)**

**Figure 8: Trends in Reported Turnover of Corporate Bonds (₹ crore)**

***टिप्पणी: केवल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए निपटाए (सेटल किए) गए ट्रेड के आँकड़े शामिल किए गए हैं***

***Note: Data Includes only settled trades through the exchange platform***

|  |  |
| --- | --- |
| **V.** **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए निवेश के रुख**   * **फ़रवरी 202**3 में, एफपीआई ने कुल मिलाकर बिक्री की, और कुल 4139 करोड़ रुपये का विनिवेश किया । इक्विटी, डेट वीआरआर और हाइब्रिड सेगमेंट में शुद्ध बहिर्वाह क्रमशः 5,294 करोड़ रुपये, 1,044 करोड़ रुपये और 237 करोड़ रुपये देखा गया, जबकि डेट सेगमेंट में 2,436 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह देखा गया। * इक्विटी सेगमेंट के भीतर, प्राथमिक बाजार के माध्यम से ₹ 289 करोड़ का प्रवाह देखा गया, जबकि द्वितीयक बाजार से ₹ ​​5,583 करोड़ की राशि का बहिर्वाह देखा गया। * **फ़रवरी 202**3 के अंत तक भारत में एफपीआई की एयूसी ₹ 48,32,772 करोड़ की रहीं, जिसमें से ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ओडीआई) [डेरिवेटिव पर ओडीआई सहित] का आनुमानिक मूल्य ₹88,398 करोड़ रहा, जो एफपीआई की कुल एयूसी का 1.83 प्रतिशत था । | 1. **Trends in Investments by the Foreign Portfolio Investors (FPIs)**  * FPIs remained net sellers in the month of February 2023 with outflows worth ₹ 4,139 crore. Net outflows were witnessed in equity, debt VRR and hybrid segments to the tune of ₹ 5,294 crore, ₹ 1,044 crore and ₹ 237 crore respectively whereas debt segment witnessed net inflows worth ₹ 2,436 crore. * Within the equity segment, inflows were observed via primary market route to the tune of ₹ 289 crore while secondary market route witnessed outflows amounting to ₹ 5,583 crore. * The AUC of FPIs in India, as at the end of February 2023 was ₹ 48,32,772 crore, out of which the notional value of offshore derivative instruments (ODIs) (including ODIs on derivatives) was ₹ 88,398 crore which constituted 1.83 per cent of total AUC of FPIs. |

**आकृति 9 : एफपीआई निवेश के रुख (₹ करोड़ में)**

**Figure 9: Trends in FPIs’ Investments** (₹ crore)

**स्रोत: एनएसडीएल**

**Source: NSDL**

|  |  |
| --- | --- |
| **VI.** संस्थागत निवेश के रुख   1. पारस्परिक निधियों द्वारा धन संग्रहण / किए गए लेनदेन की रुख  * **फ़रवरी 202**3 **के दौरान, पारस्परिक निधियों में शुद्ध आवक** ₹9,575 करोड़ की हुई, जबकि **जनवरी 202**3 मे **शुद्ध आवक** ₹11,373 करोड़ की थी । * **फ़रवरी 202**3 के दौरान, असीमित अवधि वाली योजनाओं के तहत ₹7,96,135 **करोड़ सकल राशि जुटाई गई, जबकि** ₹7,87,147 **करोड़ की राशि की यूनिटें बेची गईं/ पुनःखरीद की गई, और इस प्रकार** असीमित अवधि वाली योजनाओं के तहत शुद्ध आवक ₹8,988 करोड़ का रहा । * असीमित अवधि वाली योजनाओं की सभी **श्रेणियों** की योजनाओं के तहत जुटाई गई **सकल राशि** में से, आय/ऋण उन्मुख योजनाओं के माध्यम से ₹7,26,989 करोड़ की राशि, संवृद्धि/इक्विटी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से ₹32,476 करोड़, अन्य योजनाओं के माध्यम से ₹25,030 करोड़, संकर (हाइब्रिड) योजनाओं के माध्यम से ₹11,319 करोड़, और समाधान उन्मुख (सॉल्यूशन ओरियेंटेड) योजनाओं के माध्यम से ₹321 करोड़ की राशि जुटाई गई । * **फ़रवरी 202**3 के दौरान, सीमित अवधि वाली योजनाओं (क्लोज़ एंडेड योजनाओं) द्वारा ₹954 करोड़ और ₹135 करोड़ की राशि की यूनिटें परिपक्व हो गई / पुनःखरीद की गई। * **फ़रवरी 202**3 **के अंत तक पारस्परिक निधियों की संचयी शुद्ध प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (**असेट्स अंडर मैनेजमेंट)0.41 **प्रतिशत से घटकर** ₹**39,46,257 करोड़ हो गयी।** * **फ़रवरी 202**3 **के दौरान, द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) में, पारस्परिक निधियों ने इक्विटी योजनाओं के तहत शुद्ध** ₹12,825 **करोड़ खरीदी की और ऋण** (**डैट) योजनाओं के तहत** ₹12,868 **करोड़ शुद्ध बिक्री की, और इस तरह से शुद्ध आबक** ₹44 **करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री हुई ।** | 1. **Trends in Institutional Investments** 2. **Trends in Fund Mobilisation/ Transactions by Mutual Funds**  * The net inflow in mutual funds stood at ₹9,575 crore during February 2023 compared to net inflow of ₹11,373 crore during January 2023. * Gross funds mobilised by open-ended schemes during February 2023 was ₹7,96,135 crore as against redemption/repurchase of ₹7,87,147 crore, resulting in a net inflow of ₹8,988 crore from open-ended schemes. * Of the gross fund mobilisation across entire category of schemes under open-ended schemes, ₹7,26,989 crore was mobilised through income/debt oriented schemes, ₹32,476 crore through growth/equity oriented schemes, ₹25,030 crore through other schemes, ₹11,319 crore through hybrid schemes and ₹321 crore through solution oriented schemes. * During February 2023, ₹954 crore and ₹135 crore were mobilised and matured/repurchased[[2]](#footnote-2) respectively by close-ended schemes. * The cumulative net assets under management (AUM) of mutual funds decreased by 0.41 per cent to ₹39,46,257 crore as at the end of February 2023. * Net purchase of mutual funds in the secondary market during February 2023 was ₹12,825 crore in equity schemes and mutual funds sold a net of ₹12,868 crore in debt schemes, resulting in a net sale of ₹44 crore. |
|  |  |

**आकृति 10 : द्वितीयक बाजार में पारस्परिक निधियों द्वारा शुद्ध खरीदी / बिक्री के रुख (₹ करोड़ में)**

**Figure 10: Trends in Net Purchase/Sales of Mutual Funds Transactions in Secondary Market (₹crore)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **VII.** पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के रुख   * **फ़रवरी 202**3 **के अंत मे पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्योग की शुद्ध प्रबंधनाधीन आस्तियाँ** ₹**26.75 लाख करोड़ की रहीं, जबकि जनवरी 202**3 **के अंत में यह** ₹26.47 **लाख करोड़ की थीं। साल-दर-साल के आधार पर पोर्टफोलियो प्रबंधकों के द्वारा कुल आस्तियों** **के प्रबंधन मे** 12.49 **प्रतिशत तक का बढ़ोत्तरी हुई।** * **फ़रवरी 202**3 **के अंत में पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्योग के तहत ग्राहकों की कुल संख्या** 1,36,599 **रही, जबकि जनवरी 202**3  **के अंत में यह संख्या** 1,37,981 **थी। फ़रवरी 202**3 **के अंत तक के इन ग्राहकों में से** 1,29,010 **ग्राहक पोर्टफोलियो प्रबंधकों की** वैवेकिक सेवाएँ लेने वाले रहे, जब की 5,614 ग्राहक गैर-वैवेकिक सेवाएँ और 1,923 ग्राहक सलाहकार सेवाएँ लेने वाले रहे । | 1. **Trends in Portfolio Management Services**  * At the end of February 2023, AUM of the portfolio management industry stood at ₹26.75 lakh crore as compared to ₹26.47 lakh crore at the end of January 2023. On a year on year basis, the total asset managed by Portfolio Managers (PMs) increased by 12.49 per cent. * The number of clients in portfolio management industry was at 1,36,599 at the end of February 2023 compared to 1,37,981 at the end of January 2023. Out of the total number of clients at the end of February 2023, 1,29,010 clients were of discretionary services category, 5,614 clients in non-discretionary services category and 1,923 clients availed advisory services of portfolio managers. |   आकृति 11: पोर्टफोलियो प्रबंधकों के ग्राहकों की संख्या और उनकी प्रबंधनाधीन आस्तियाँ  **Figure 11: Number of Clients and AUM of Portfolio Managers**  *टिप्पणी : जनवरी 2022 के आँकड़े 312 पीएमएस द्वारा 1 फरवरी, 2023 तक प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार दिए गए हैं । नवम्बर 2022 के आँकड़ों में 314 पीएमएस द्वारा 1 फरवरी, 2023 तक प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार बदलाव किया गया है ।*  *Note: The data for the month of December 2022 is as per submissions made by 312 PMSs till February 1, 2023. Data for the month of November 2022 is revised as per submisison made by 314 PMSs till February 1, 2023.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VIII.** शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण:   * **फरवरी 202**3 **के दौरान,** [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011](http://www.sebi.gov.in/sebihindi/Regulation_h/Reg48_h/Reg48_h.html) **के तहत 5 खुले प्रस्ताव बंद हुए, जिनका मूल्य** ₹ 299 **करोड़ का था।** | 1. **Trends in Substantial Acquisition of Shares and Takeovers**  * During February 2023, 5 open offers with offer value of ₹ 299 crore closed under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011. |

आकृति **12 : उन खुले प्रस्तावों (ओपन ऑफर) के ब्यौरे, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत बंद किया गया**

**Figure 12: Details of Open Offers Closed under the SEBI (SAST) Regulations**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार 2. बाजार के रुख  * **फरवरी 202**3 **के अंत मे, एमसीएक्स के आईकॉमडेक्स कम्पोज़िट सूचकांक में, पिछले महीने की तुलना में** 4.2 **प्रतिशत तक की** गिरावट **हुई।** * **क्षेत्रो के सूचकांकों में, एमसीएक्स आईकॉमडेक्स मेटल सूचकांक में 6.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जबकि एमसीएक्स आईकॉमडेक्स** **बुलियन सूचकांक और एमसीएक्स आईकॉमडेक्स एनर्जी सूचकांक में 3.9 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ ।** * **भारत के कमोडिटी सूचकांकों में पिछले 12 महीनों के दौरान हुए उतार-चढ़ाव को** *आकृति 14* **में दर्शाया गया है। एमसीएक्स के आईकॉमडेक्स कम्पोज़िट सूचकांक के मासिक आंकड़े** *सारणी 65* **में दर्शाए गए हैं ।** | **IX. Commodity Derivatives Market**   1. **Market Trends**  * At the end of February 2023, MCX iCOMDEX composite index decreased by 4.2 per cent (M-o-M). * Amongst sectoral indices, MCX iCOMDEX Metal Index decreased most by 6.3 per cent, while MCX iCOMDEX Bullion index and MCX iCOMDEX Energy index also decreased by 3.9 per cent and 2.2 per cent, respectively. * Movement of domestic commodity indices during the last 12 months is given in ***Figure 14.*** The monthly data of MCX’s iCOMDEX composite index is provided in ***Table 65.*** |

आकृति 13 : देश के कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार के सूचकांकों में हुआ उतार-चढ़ाव

**Figure 13: Movement of Domestic Commodity Derivatives Market Indices**

टिप्पणी : सूचकांक को 31 दिसम्बर, 2021 के मूल्यों के अनुसार नॉर्मलाइज़ किया गया है ।

Note: The index has been normalised to the values as at Dec 31, 2021

स्रोत: एमसीएक्स

Source: MCX

**सारणी 4: भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार – एक नज़र में**

**Table 4: Snapshot of Indian Commodity Derivatives Markets**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **मद /**  **Items** | जनवरी **/ Jan-23** | **फरवरी / Feb-23** | **माह-दर-माह परिवर्तन (प्रतिशत में)**  **Percentage variation M-O-M** |
| **1. सूचकांक / Indices** |  |  |  |
| एमसीएक्स आईकॉमडेक्स  MCX iCOMDEX | 13,581 | 13,010 | *-4.2* |
| बुलियन / Bullion | 15,707 | 15,089 | *-3.9* |
| आधार धातुएँ / Base Metals | 19,210 | 17,916 | *-6.7* |
| ऊर्जा / Energy | 6,311 | 6,164 | *-2.3* |
| एनसीडीईएक्स ग्वारेक्स NCDEX Guarex | 7,714 | 7,700 | *-0.2* |
| **2. व्यापारावर्त (टर्नओवर) - एक्सचेंजों के अनुसार / Turnover Exchange Wise (₹ करोड़ में / ₹ crore)** | | | |
| **भारत के सभी एक्सचेंजों का**  **All-India** | **12,13,974** | **13,29,376** | *9.5* |
| **एमसीएक्स, जिसमें से**  **MCX, of which** | **11,91,774** | **13,13,658** | *10.2* |
| फ्यूचर्स / Futures | 4,22,517 | 4,13,579 | *-2.1* |
| ऑप्शन्स / Options | 7,69,257 | 9,00,079 | *17.0* |
| **बीएसई, जिसमें से**  **BSE, of which** | **194** | **167** | *-14.1* |
| फ्यूचर्स / Futures | 134 | 113 | *-15.7* |
| ऑप्शन्स / Options | 60 | 54 | *-10.5* |
| **एनसीडीईएक्स, जिसमें से**  **NCDEX, of which** | **20,953** | **14,527** | *-30.7* |
| फ्यूचर्स / Futures | 20,953 | 14,527 | *-30.7* |
| ऑप्शन्स / Options | 0 | 0 | *-* |
| **एनएसई, जिसमें से**  **NSE, of which** | **1053** | **1025** | *-2.6* |
| फ्यूचर्स / Futures | 1 | 1 | *0.0* |
| ऑप्शन्स / Options | 1051 | 1024 | *-2.6* |

**स्रोत: एमसीएक्स, बीएसई, एनसीडीईएक्स, एनएसई**

**Source: MCX, BSE, NCDEX, NSE**

|  |  |
| --- | --- |
| **कमोडिटी डेरिवेटिव का व्यापारावर्त (टर्नओवर)**   * **फरवरी** 2023 के दौरान, पूरे भारत मे कमोडिटी व्युत्पन्नी की व्यापारावर्त पिछले महीने की तुलना में 9.5 प्रतिशत बढ़कर र ₹13.3 लाख करोड़ की हो गयी । * कृषि खंड के व्यापारावर्त में 30 प्रतिशत की कमी आई जबकि गैर-कृषि खंड में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। * कृषि और कृषि से इतर खंडों के व्यापारावर्त में क्रमशः 1.1 प्रतिशत और 98.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। * कुल व्यापारावर्त में फ्यूचर्स और ऑप्शन्स कॉण्ट्रैक्ट की हिस्सेदारी क्रमशः 32.2 प्रतिशत और 67.8 प्रतिशत की रही । पिछले महीने की तुलना में, फ्यूचर्स कॉण्ट्रैक्ट की व्यापारावर्त मे 3.5 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई और ऑप्शन्स में 17 प्रतिशत बढ़त दर्ज हुई। * एक्सचेंजों की बात करें, तो पिछले महीने की तुलना में एनएसई के टर्नओवर में 10.2 प्रतिशत तक की बढ़त हुई, जबकि बीएसई, एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स के टर्नओवर में क्रमशः 14.1 प्रतिशत 30.7 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई। * एक्सचेंजों मे कमोडिटी डेरिवेटिव के व्यापारावर्त में हिस्सेदारी के लिहाज से, एमसीएक्स की हिस्सेदारी 98.8 प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा रही, उसके बाद एनसीडीईएक्स की 1.1 प्रतिशत, एनएसई की 0.08 प्रतिशत और बीएसई की 0.01 प्रतिशत रही। * **एमसीएक्स** में**, कृषि के** व्यापारावर्त **में कपास कैंडी** कॉण्ट्रैक्ट **की शुरूआत के कारण 50.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-कृषि में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेगमेंट टर्नओवर के लिए जिम्मेदार कच्चे तेल के ऑप्शन** कॉण्ट्रैक्ट **के टर्नओवर में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि को ठहराया जा सकता है।** * एनसीडीईएक्स में, पिछले महीने की तुलना में कुल टर्नओवर 30.7 प्रतिशत घटकर ₹14,527 करोड़ रह गयी। इसके लिए जीरा, धनिया और कपास के व्यापारावर्त में क्रमशः 48.7 प्रतिशत, 46.3 प्रतिशत और 39.8 प्रतिशत की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। * बीएसई में ₹167 करोड़ का (टर्नओवर) दर्ज हुआ, जो पिछले महीने की तुलना में 14.1 प्रतिशत कम रहा। कुल व्यापारावर्त में फ्यूचर्स कॉण्ट्रैक्ट की हिस्सेदारी 67.8 प्रतिशत (₹113 करोड़) की रही, जबकि ऑप्शन्स कॉण्ट्रैक्ट की हिस्सेदारी 32.2 प्रतिशत (₹54 करोड़) की रही । ऑप्शन्स के व्यापारावर्त में, गोल्ड मिनी कॉण्ट्रैक्ट की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी रही । * एनएसई में ₹1,025 करोड़ रुपये का व्यापारावर्त दर्ज हुआ, जो पिछले महीने की तुलना में 2.6 प्रतिशत कम रहा। एनएसई के व्यापारावर्त में गोल्ड मिनी कॉण्ट्रैक्ट के ऑप्शन्स कॉण्ट्रैक्ट् की ही लगभग पूरी हिस्सेदारी रही। * एक्सचेंजों में कमोडिटी डेरिवेटिव के व्यापारावर्त के रुख आकृति 15, 16 और 17 में दर्शाए गए हैं और इनसे संबंधित ब्यौरे सारणी 66 से 69 में दिए गए हैं । | **Commodity Derivatives Turnover**   * During February 2023, pan- India turnover of all commodity derivatives contracts increased by 9.5 per cent to ₹13.3 lakh crore over the previous month. * The turnover of agri. segment decreased by 30 per cent while that of non-agri segment increased by 10.2 per cent. * The percentage share of agri and non-agri segments in overall turnover accounted for 1.1 per cent and 98.9 per cent, respectively.      * The percentage share of futures and options contracts in overall turnover stood at 32.2 per cent and 67.8 per cent, respectively. The turnover of futures contracts decreased by 3.5 per cent and that of options increased by 17 per cent over the previous month. * At exchange level, the turnover has increased for MCX by 10.2 per cent. However, the turnover declined for BSE, NCDEX, and NSE by 14.1 per cent, 30.7 per cent and 2.6 per cent, respectively (M-o-M). * In terms of percentage share of commodity derivatives turnover among exchanges, the MCX has the highest market share of 98.8 per cent, followed by NCDEX (1.1 per cent), NSE (0.08 per cent) and BSE (0.01 per cent). * At MCX, the turnover of agri. segment increased by 50.3 per cent on account of introduction of Cotton Candy contract, while 10.2 per cent rise in non-agri. segment turnover may be attributed to 30.5 per cent increase in turnover of Crude Oil options contracts. * At NCDEX, the overall turnover decreased by 30.7 per cent to ₹14,527 crore over the previous month. This can be attributed to the reduction in turnover of Jeera, Coriander, and Kapas by 48.7 per cent, 46.3 per cent, and 39.8 per cent, respectively. * The BSE recorded turnover of ₹167 crore, which is a decline of 14.1 per cent from the previous month. The futures contracts contributed 67.8 per cent (₹113 crore), while options contracts contributed 32.2 per cent (₹54 crore) to the total turnover. In the category of options, gold mini contracts solely contributed to the turnover. * NSE recorded turnover of ₹1,025 crore, a decrease of 2.6 per cent over the previous month. The options on gold mini contracts contributed to almost all of the turnover in the commodity derivatives segment. * The trends in turnover of commodity derivatives at exchanges are shown in Figures 15, 16 and 17 and the details are given in Tables 66 to 69. |

**आकृति 14: कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख**

**Figure 14: Trends in Turnover of Agricultural Commodity Derivatives**

**स्रोत: एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, एनएसई, बीएसई**

**Source: MCX, NCDEX, NSE, BSE**

आकृति 15: कृषि से इतर फ्यूचर्स कॉण्ट्रैक्ट के व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख

**Figure 15: Trends in Turnover of Non-Agricultural Futures contracts**

स्रोत: एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, एनएसई, बीएसई

**Source: MCX, NCDEX, NSE, BSE**

आकृति 16: कृषि से इतर ऑप्शन्स कॉण्ट्रैक्ट के व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख

**Figure 16: Trends in Turnover of Non-Agricultural Options contracts**

**स्रोत: एमसीएक्स, बीएसई, एनएसई**

**Source: MCX, BSE, NSE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वैश्विक वित्तीय बाजारों की समीक्षा  **अर्थव्यवस्था की स्थिति**  **वैश्विक अर्थव्यवस्था/**   * वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, दुनिया भर में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की स्तर और उसके बाद उसको काबू करने के लिए सख्त मौद्रिक उपायों से लेकर पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक विकास के परिणाम और उसके आगामी ऊर्जा संकट और हाल ही में तुर्की में प्राकृतिक आपदा। हालाँकि, हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में एक नई चुनौती उभर कर सामने आई है। * फेड द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि के परिणामस्वरूप ट्रेजरी बॉन्ड की प्रतिफल में उछाल आया है जिससे उनकी कीमतें नीचे आ गई हैं। जब ट्रेजरी बॉन्ड में भारी निवेश करने वाले बैंकों के ग्राहकों ने विश्वास खो दिया और पैसा निकालना शुरू कर दिया तो अधिक से अधिक लोग इस अंधानुकरण में शामिल हो गए, तो बैंकों को तरलता संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी संपत्ति (जिसका मूल्य खो गया था) उनके देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी लिए एक सप्ताह के भीतर तीन अमेरिकी बैंक विफल हो गये। अब, उनमें से एक, सिलिकॉन वैली बैंक टेक कंपनियों और स्टार्ट-अप्स के लिए एक प्रमुख डिपॉजिटरी थी और भारत-अमरीकी बाज़ार में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऋणदाता थी । यह आशंका है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली प्रभावित हो सकती है यदि अमेरिकी बाजार पर निर्भर भारतीय निर्यातकों को अपने व्यवसायों में मंदी दिखाई देने लगे, जिससे नौकरी की वृद्धि और उनके बैंकों को ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित करेगा। भारत में आने वाले उद्यम पूंजी निवेश का प्रवाह धीमा हो सकता है। * इसी दौरान मंदी के डर के बीच, सर्वेक्षण सूचकांकों ने कुछ सकारात्मक तस्वीरें पेश कीं,वैश्विक आर्थिक गतिविधि में फरवरी 2023 के दौरान छह महीने के लंबे संकुचन को समाप्त करते हुए विस्तार देखा गया। व्यापार सेवाओं, उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और निवेश वस्तुओं में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। हालांकि इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक उज्ज्वल स्थान के रूप में खड़ी है, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि हाल के घटनाक्रमों के कारण विकास की गति कुछ हद तक बाधित हो सकती है जैसा कि ऊपर बताया गया है। * फरवरी 2023 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, जिससे सर्वेक्षण के संकेतकों से पता चलता है कि संकुचन का छह महीने का क्रम समाप्त हो गया। जेपी मॉर्गन ग्लोबल कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स फरवरी 2023 में 52.1 रहा, जो जनवरी 2023 में 49.7 था, यानी तटस्थ 50.0 अंक से ऊपर। जेपी मॉर्गन ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स ने जुलाई 2022 के बाद पहली बार वृद्धि का संकेत दिया, क्योंकि यह फरवरी 2023 में 52.6 के आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो जनवरी 2023 में तटस्थ 50.0 अंक से ऊपर था। विनिर्माण क्षेत्र में भी देखा गया। गतिविधि में वृद्धि। J.P.Morgan ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI ने फरवरी 2023 में 50.0 की रीडिंग पोस्ट की, जो नो-चेंज मार्क के समान है, जनवरी 2023 में 49.1 से ऊपर, सिग्नलिंग संकुचन के पांच महीने के रन को रोकते हुए।   **संयुक्त अमेरिका**   * आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो के "दूसरे" अनुमान के अनुसार, अमेरिका का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022 की चौथी तिमाही के दौरान 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.7 प्रतिशत (क्यू-ओ-क्यू) की वार्षिक दर से बढ़ा Q3 2022 है। * अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2023 में 6.4 प्रतिशत से कम होकर फरवरी 2023 में 6 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2021 के बाद सबसे कम है। बेरोजगारी दर जनवरी 2023 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2023 में 3.6 प्रतिशत हो गई। * फ्लैश यूएस कम्पोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स ने फरवरी 2023 में 50.2 दर्ज किया, जो जनवरी 2023 में सेवा क्षेत्र की गतिविधि द्वारा संचालित 46.8 से तेजी से बढ़ा। अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र की सेहत में फरवरी 2023 के दौरान धीमी गति से गिरावट जारी रही। एसएंडपी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने फरवरी 2023 में 47.3 पोस्ट किया, जनवरी 2023 में 46.9 से थोड़ा ऊपर। एसएंडपी ग्लोबल यूएस सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स ने फरवरी 2023 में 50.6 दर्ज किया, जो जनवरी 2023 में 46.8 से विशेष रूप से दर्ज किया गया था, जो पूरे व्यापार गतिविधि में नए सिरे से विस्तार का संकेत देता है। अमेरिकी सेवा क्षेत्र।   **यूनाइटेड किंगडम**   * ऑफिस ऑफ़ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के पहले तिमाही अनुमानों के अनुसार, यूके की वास्तविक जीडीपी Q4 2022 में स्थिर (तिमाही-दर-तिमाही) थी, जबकि Q3 2022 में 0.2 प्रतिशत का संकुचन हुआ था। * उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दिसंबर 2022 के 10.5 प्रतिशत से गिरकर जनवरी 2023 में 10.1 प्रतिशत पर आ गया। * यूके में बेरोजगारी दर पिछले तीन महीनों की तुलना में नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान 3.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। * फरवरी 2023 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 50 बीपीएस से 4.0 प्रतिशत की वृद्धि की, जिससे उधार लेने की लागत 2008 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि नीति निर्माता महंगाई के डर के बीच मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। * ब्रिटेन की निजी क्षेत्र की कंपनियों ने फरवरी के दौरान व्यापारिक गतिविधि में ठोस वापसी का संकेत दिया, जिससे उत्पादन में गिरावट के छह महीने की अवधि समाप्त हो गई। विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों ने विकास की वापसी हासिल की, जिसमे सेवा क्षेत्र ने विस्तार की तेज दर दर्ज की। एसएंडपी ग्लोबल सीआईपीएस फ्लैश यूके कम्पोजिट पीएमआई जनवरी 2023 में 48.5 से फरवरी 2023 में 53.0 दर्ज किया गया। सेवा पीएमआई जनवरी 2023 में 48.7 से फरवरी 2023 में 53.5 पर पहुंच गया, जो सेवा क्षेत्र की गतिविधि में काफी गति का संकेत देता है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने फरवरी 2023 में 49.3 दर्ज किया, जो जनवरी 2023 में 47.0 था, जो एक लचीला प्रदर्शन दिखा रहा है।   **यूरो क्षेत्र**   * यूरोस्टेट (यूरोपीय संघ के सांख्यिकीय कार्यालय) द्वारा जारी जीडीपी के अनुमानों के अनुसार, यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था ने 2022 की अंतिम तिमाही में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के प्रारंभिक अनुमानों और ऊपर की ओर संशोधित 0.4 प्रतिशत विस्तार की तुलना में कोई वृद्धि नहीं दिखाई। पिछले तीन महीने की अवधि। * प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, यूरो क्षेत्र में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2023 में 8.6 प्रतिशत से गिरकर 2023 के फरवरी में 8.5 प्रतिशत हो गई। * जनवरी 2023 में यूरो क्षेत्र की मौसमी-समायोजित बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 के समान ही 6.7 प्रतिशत थी। * यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी मार्च 2023 की बैठक के दौरान मुख्य पुनर्वित्त संचालन पर ब्याज दर को 50 बीपीएस से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया, जिससे उधार लेने की लागत 2008 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।   **भारत**   * राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दूसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार, भारत की वास्तविक GDP 2022-23 के दौरान 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान तिमाही वास्तविक जीडीपी पिछली तिमाही के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 4.4 प्रतिशत बढ़ी। * सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2023 में 6.52 प्रतिशत से फरवरी 2023 में थोड़ी धीमी होकर 6.44 प्रतिशत हो गई। * MOSPI द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, जनवरी 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 5.2 प्रतिशत (Y-o-Y) की वृद्धि हुई, जबकि दिसंबर 2022 के दौरान 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। * भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी फरवरी 2023 की बैठक के दौरान अपनी प्रमुख रेपो दर को 25 बीपीएस से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया, जो वर्तमान विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर लगातार छठी दर वृद्धि है। नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गई है। * पीएमआई सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि जहां फरवरी 2023 के दौरान सेवा क्षेत्र ने मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, वहीं विनिर्माण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बिक्री विस्तार की दर में उल्लेखनीय मंदी का सामना करना पड़ा। मौसमी रूप से समायोजित एस एंड पी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फरवरी 2023 में 55.3 पर था, जो जनवरी 2023 में 55.4 से थोड़ा-सा बदला हुआ था, जो क्षेत्र के स्वास्थ्य में एक मजबूत सुधार का संकेत देता है (शीर्षक का आंकड़ा भी इसके लंबे समय तक चलने वाले औसत 53.7 से ऊपर था)। फरवरी 2023 में 59.5 पोस्ट करना (जनवरी 2013 में 57.2 की तुलना में), मौसमी रूप से समायोजित एस एंड पी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर था और आउटपुट में तेज विस्तार का संकेत दिया   **बाजार के रुझान**  इक्विटी बाजार   * फरवरी 2023 में ब्रिक्स देशों (रूस को छोड़कर) के बीच, ब्राजील के iBovespa (17.0 प्रतिशत) में उच्चतम वार्षिक अस्थिरता देखी गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के FTSE/JSE अखिल अफ्रीका सूचकांक (15.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। * सूचकांकों के मासिक रिटर्न के संदर्भ में, चीन के शंघाई एसई कंपोजिट सूचकांक को छोड़कर, ब्रिक्स देशों (रूस को छोड़कर) के अन्य सभी सूचकांकों ने नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया। शंघाई एसई कंपोजिट सूचकांक 0.7 प्रतिशत बढ़ा। ब्राजील के iBovespa ने 7.5 प्रतिशत का नकारात्मक मासिक रिटर्न दर्ज किया, इसके बाद FTSE/JSE अफ्रीका ऑल शेयर इंडेक्स (-2.2 प्रतिशत) और निफ्टी 50 (-2.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। * चुनिंदा विकसित बाजार सूचकांकों में1, संयुक्त राज्य अमेरिका के NASDAQ कंपोजिट में 23.2 प्रतिशत की उच्चतम वार्षिक अस्थिरता देखी गई, इसके बाद हांगकांग का हैंग सेंग (16.4 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया का कोस्पी रहा। * चुनिंदा विकसित बाजार सूचकांकों में मिलाजुला रुख रहा। फ्रांस का CAC 40 2.6 प्रतिशत बढ़ा, उसके बाद जर्मनी का Dax (1.6 प्रतिशत), जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 9.4 प्रतिशत गिर गया और उसके बाद USA का डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (4.2 प्रतिशत) रहा। * MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, जिसे 23 विकसित और 24 उभरते बाजारों में बड़े और मिड-कैप शेयरों के पूर्ण अवसर सेट के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फरवरी 2023 के अंत में स्तर से 3.0 प्रतिशत कम हो गया। जनवरी 2023. उसी समय, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, जो 23 विकसित बाजारों के देशों में लार्ज और मिड-कैप प्रतिनिधित्व पर कब्जा करता है, 2.5 प्रतिशत गिर गया। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो 24 उभरते बाजारों वाले देशों में लार्ज और मिड-कैप का प्रतिनिधित्व करता है, 6.5 प्रतिशत बढ़ा। |  | **OVERVIEW OF THE GLOBAL FINANCIAL MARKETS** **State of Economy**  **Global Economy**   * The global economy is facing a plethora of challenges ranging from elevated worldwide inflation levels and subsequent monetary tightening measures, to the consequences of the geopolitical developments in Eastern Europe and the ensuing energy crisis to the recent natural calamity in Turkey. However, pretty recently a new challenge in the financial sector has surfaced. * Aggressive increase of interest rate by the Fed has resulted in jumping of the Treasury bond yields pushing their prices down. When customers of banks having huge investment in Treasury bonds lost confidence and started to withdraw money and more and more people joined the bandwagon, the banks faced liquidity crisis as their assets (which had lost value) were not sufficient to pay their liabilities. Thus the world saw failure of three US banks within the span of one week. Now, one of them, the Silicon Valley Bank was a major depository to tech companies and start-ups and a significant lender to companies doing business in the US-India market. It is feared that Indian financial system could get impacted if Indian exporters dependent upon US market start seeing slowdown in their businesses, which would impact job growth and ability to repay debt to their banks. The flow of venture capital investment coming into India might slow down. * Amid the fear of looming recession, the survey indices pose some positive pictures as global economic activity witnessed expansion during February 2023, ending six-month long contraction. Economic activity expanded in business services, consumer goods, consumer services, financial services and investment goods. Although Indian economy stands as a bright spot amid this gloomy outlook, economists forecast that the growth tempo may be somewhat thwarted owing to the recent developments as enumerated above. * The global economic activities went up in February 2023, ending six-month sequences of contraction as reflected by the survey indicators. The J.P.Morgan Global Composite Output Index posted 52.1 in February 2023, up from 49.7 in January 2023, i.e. a reading above the neutral 50.0 mark. The J.P.Morgan Global Services Business Activity Index signalled growth for the first time since July 2022 as it rose to an eight-month high of 52.6 in February 2023, up from a reading at the neutral 50.0 mark in January 2023. The manufacturing sector too witnessed increase in activity. The J.P.Morgan Global Manufacturing PMI posted a reading 50.0 in February 2023, identical to the no-change mark, up from 49.1 in January 2023, halting a five-month run of signalling contraction.   **United States**   * According to the “second” estimate by Bureau of Economic Analysis, the real Gross Domestic Product (GDP) of the US increased at an annual rate of 2.7 per cent (Q-o-Q) during the fourth quarter of 2022, as compared to 3.2 per cent growth in Q3 2022. * The annual inflation rate in the US slowed to 6 per cent in February 2023 from 6.4 per cent in January 2023, the lowest since September 2021. The unemployment rate edged up to 3.6 per cent during February 2023 from 3.4 per cent in January 2023. * The Flash US Composite PMI Output Index posted registered 50.2 in February 2023, sharply up from 46.8 in January 2023 driven by the services sector activity. The health of the US manufacturing sector continued to decline during February 2023 albeit at a slower pace. The S&P Global US Manufacturing PMI posted 47.3 in February 2023, slightly up from 46.9 in January 2023. The S&P Global US Services PMI Business Activity Index registered 50.6 in February 2023, up notably from 46.8 in January 2023 indicating a renewed expansion in business activity across the US service sector.   **United Kingdom**   * As per the first quarterly estimates by Office of National Statistics, the real GDP of the UK was stagnant (Q-o-Q) in Q4 2022, as compared to a contraction of 0.2 per cent in Q3 2022. * The Consumer Price Index (CPI) fell to 10.1 per cent in January 2023 from 10.5 per cent in the December 2022 * The unemployment rate in the UK remained unchanged at 3.7 per cent during November 2022 to January 2023 compared to previous three months. * In its Monetary Policy meeting held in February 2023, the Bank of England raised interest rates by 50 bps to 4.0 per cent, pushing the cost of borrowing to the highest level since late-2008, as policymakers try to contain inflation amid fears of a looming economic recession. * UK private sector firms signalled a solid rebound in business activity during February, which ended a six month period of falling output. Both the manufacturing and service sectors achieved a return to growth, with the latter posting the faster rate of expansion. The S&P Global CIPS Flash UK Composite PMI posted 53.0 in February 2023 from 48.5 in January 2023. The Services PMI jumped to 53.5 in February 2023 from 48.7 in January 2023, indicating a considerable momentum in the services sector activity. The Manufacturing PMI posted 49.3 in February 2023 up from 47.0 in January 2023 showing a resilient performance.   **Euro area**   * As per the estimates of GDP released by Eurostat (the statistical office of the European Union), the Eurozone economy showed no growth in the final quarter of 2022, compared with preliminary estimates of 0.1 per cent growth and upwardly revised 0.4 per cent expansion in the previous three-month period. * As per the preliminary estimates, annual inflation rate in the euro area inched down to 8.5 per cent in February of 2023 from 8.6 per cent in January 2023. * The euro area seasonally-adjusted unemployment rate stood at 6.7 per cent in January 2023, same with December 2022. * The European Central Bank raised the interest rate on the main refinancing operations by 50 bps to 3.5 per cent during its March 2023 meeting, pushing up borrowing costs to the highest level since late 2008.   **India**   * As per the Second Advanced Estimates by the National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation, Real GDP of India is estimated to grow by 7 per cent during 2022-23. The quarterly real GDP during the Q3 2022-23 grew by 4.4 per cent compared to 6.3 per cent in the previous quarter. * All India inflation rate based on CPI (general) slowed slightly to 6.44 per cent in February 2023 from 6.52 per cent in January 2023 * As per quick estimates released by MOSPI, Index of Industrial Production (IIP) increased by 5.2 per cent (Y-o-Y) in January 2023, compared to a growth of 4.3 per cent during December 2022. * The Reserve Bank of India raised its key repo rate by 25 bps to 6.50 per cent during its February 2023 meeting, the sixth rate hike in a row on the basis of an assessment of the current evolving macroeconomic situation. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 6.25 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 6.75 per cent. * The PMI survey data show that while service sector exhibited robust growth during February 2023, the manufacturing sector faced notable slowdown in the rate of international sales expansion. The seasonally adjusted S&P Global India Manufacturing PMI was at 55.3 in February 2023, little-changed from 55.4 in January 2023 signalling a strong improvement in the health of the sector (the headline figure was also above its long-run average of 53.7). Posting 59.5 in February 2023 (as compared to 57.2 in January 2013), the seasonally adjusted S&P Global India Services PMI was at its highest level in 12 years and indicated a sharp expansion in output   **Market Trends**  **Equity Markets**   * In February 2023, amongst the BRICS countries (excluding Russia), highest annualized volatility was observed in iBovespa of Brazil (17.0 per cent) followed by FTSE/JSE All Africa index of South Africa (15.1 per cent). * In terms of monthly return of indices, barring Shanghai SE Composite index of China, all other indices of BRICS countries (excluding Russia) recorded negative return. The Shanghai SE Composite index increased by 0.7 per cent. iBovespa of Brazil recorded a negative monthly return of 7.5 per cent, followed by FTSE/JSE Africa All Share Index (-2.2 per cent) and Nifty 50 (-2.0 per cent). * Among select developed market indices[[3]](#footnote-3), NASDAQ COMPOSITE of USA witnessed the highest annualised volatility of 23.2 per cent, followed by Hang Seng of Hong Kong (16.4 per cent) and Kospi of South Korea. * There was a mixed trend among select developed market indices. CAC 40 of France increased by 2.6 per cent, followed by Dax of Germany (1.6 per cent), while Hang Seng of Hong Kong fell by 9.4 per cent followed by Dow Jones Industrial Average of the USA (4.2 per cent). * The MSCI All Country World Price Index, designed to represent performance of the full opportunity set of large and mid-cap stocks across 23 developed and 24 emerging markets, decreased by 3.0 per cent at the end of February 2023 from the level at the end of January 2023. During the same time, the MSCI World Index, which captures large and mid-cap representation across 23 developed markets countries, fell by 2.5 per cent. The MSCI Emerging Market Index, which captures large and mid-cap representation across 24 emerging markets countries, increased by 6.5 per cent |

**तालिका 1: स्टॉक सूचकांकों का प्रदर्शन**

**Table 1: Performance of Stock Indices**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Country** | **Name of the Index** | **Closing Value as on** | **Percentage change in Closing Value over period** | | | | **Volatility (%)** | **P/E Ratio** |
| **28-Feb-23** | **1-Month** | **3-Month** | **6-Month** | **1-Year** |
| **BRICS Nations** | | | | | | | | |
| Brazil | BRAZIL IBOVESPA | 1,04,932 | -7.5 | -6.7 | -4.2 | -7.3 | 17.0 | 6.0 |
| India | Nifty 50 | 17,304 | -2.0 | -7.8 | -2.6 | 3.0 | 9.8 |  |
| India | S&P BSE SENSEX | 58,962 | -1.0 | -6.6 | -1.0 | 4.8 | 10.1 |  |
| China | SHANGHAI SE COMPOSITE | 3,280 | 0.7 | 4.1 | 2.4 | -5.3 | 12.0 | 12.0 |
| South Africa | FTSE/JSE AFRICA ALL SHR | 77,734 | -2.2 | 3.9 | 15.6 | 2.2 | 15.1 | 9.5 |
| **Developed Markets** | | | | | | | | |
| USA | NASDAQ COMPOSITE | 11,456 | -1.1 | -0.1 | -3.1 | -16.7 | 23.2 | NA |
| USA | DOW JONES INDUS. AVG | 32,657 | -4.2 | -5.6 | 3.6 | -3.6 | 11.4 | 19.6 |
| France | CAC 40 | 7,268 | 2.6 | 7.9 | 18.7 | 9.1 | 13.7 | 12.5 |
| Germany | DAX | 15,365 | 1.6 | 6.7 | 19.7 | 6.3 | 13.3 | 13.4 |
| UK | FTSE 100 | 7,876 | 1.3 | 4.0 | 8.1 | 5.6 | 8.4 | 11.7 |
| Hong Kong | HANG SENG | 19,786 | -9.4 | 6.4 | -0.8 | -12.9 | 16.4 | 10.9 |
| South Korea | KOSPI | 2,413 | -0.5 | -2.4 | -2.4 | -10.6 | 15.8 | NA |
| Japan | NIKKEI 225 | 27,446 | 0.4 | -1.9 | -2.3 | 3.5 | 9.1 | 15.0 |
| Singapore | STRAITS TIMES STI | 3,263 | -3.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 9.2 | 10.8 |
| Taiwan | TAIWAN TAIEX | 15,504 | 1.6 | 4.2 | 2.7 | -12.2 | 12.6 | 11.0 |

नोट**: पी/ई अनुपात महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार हैं।**

एनए**: उपलब्ध नहीं है**

**सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आंकड़े संबंधित एक्सचेंज की वेबसाइट से लिए गए हैं।**

स्रोत: **रिफिनिटिव, बीएसई और एनएसई**

**Note:** P/E Ratios are as on the last trading day of month.

**NA:** Not Available

Data for Sensex and Nifty were taken from respective exchange website.

**Source:** Refinitiv, BSE and NSE

**चित्र 1: चुनिंदा स्टॉक मार्केट सूचकांकों में रुझान**

**Figure 1: Trends in Select Stock Market Indices**

नोट: **सभी सूचकांकों को 31 जनवरी, 2022 को 100 पर अनुक्रमित किया गया है।**

**Note**: All indices have been indexed to 100 on January 31, 2022.

स्रोत**: रिफिनिटिव Source**: Refinitiv

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| बांड बाजार   * ब्रिक देशों में, फरवरी 2023 के अंत में, ब्राजील में उच्चतम 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल (13.3 प्रतिशत) और सबसे कम चीन (2.9 प्रतिशत) में देखा गया। * फरवरी 2023 के अंत में भारतीय 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल 7.5 प्रतिशत पर मध्यम था। * चुनिंदा विकसित देशों में, अमेरिका में 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल जनवरी 2023 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2023 में 3.9 प्रतिशत हो गया। उसी समय के दौरान ब्रिटेन में 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल भी 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया |  | **Bond Market**   * Among BRIC Nations, at the end of February 2023, highest 10-year government bond yield was observed in Brazil (13.3 per cent) and the lowest in China (2.9 per cent). * Indian 10-year government bond yield was moderate at 7.5 per cent at the end of February 2023. * Among select developed countries[[4]](#footnote-4), 10-year government bond yield in the US increased to 3.9 per cent in February 2023 from 3.5 per cent in January 2023. The yield of 10-year government bond in the UK also increased to 3.8 per cent from 3.3 per cent during the same time. |

**तालिका 2: 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल**

**Table 2: 10-year Government Bond Yields**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Country** | **Yield as on** | **Bond Yield in previous period** | | | |
| **28-Feb-23** | **1-Month** | **3-Month** | **6-Month** | **1-Year** |
| **BRIC Nations** | | | | | |
| Brazil | **13.3** | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 11.3 |
| Russia | **11.0** | 10.6 | 10.1 | 9.4 | 12.8 |
| India | **7.5** | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 |
| China | **2.9** | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
| **Developed Markets** | | | | | |
| USA | **3.9** | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 1.8 |
| UK | **3.8** | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 1.4 |
| Germany | **2.6** | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.2 |
| Spain | **3.7** | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 1.1 |
| Japan | **0.5** | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |

स्रोत**: रिफिनिटिव Source:** Refinitiv

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| मुद्रा बाज़ार   * फरवरी 2023 में, ब्रिक्स देशों के बीच सभी मुद्राओं में यूएसडी के मुकाबले मूल्यह्रास हुआ। रूसी रूबल 6.3 प्रतिशत गिर गया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का रैंड (5.5 प्रतिशत) रहा। महीने के दौरान, चयनित विकसित देशों की मुद्राओं में भी अमरीकी डालर के मुकाबले मूल्यह्रास हुआ। जापान का येन 4.7 प्रतिशत गिर गया, इसके बाद स्विस फ्रैंक (2.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। |  | **Currency Market**   * In February 2023, among BRICS nations all currencies depreciated against USD. Russian Rouble fell by 6.3 per cent, followed by Rand of South Africa (5.5 per cent). During the month, currencies of selected developed countries too depreciated against USD. Yen of Japan fell by 4.7 per cent, followed by the Swiss Franc (2.8 per cent). |

**Table 3: Movement in Major Currencies across Developing and Developed Markets**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Country** | **Currency** | **Index as on** | **Percentage change in Currency Index over period** | | | |
|  | **28-Feb-23** | **1-Month** | **3-Month** | **6-Month** | **1-Year** |
| **BRICS Nations** | | | | | | |
| Brazil | Real | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Russia | Rouble | 75.0 | 6.3 | 24.0 | 27.2 | -25.7 |
| India | Rupee | 82.6 | 1.1 | 1.6 | 4.0 | 9.5 |
| China | Renminbi | 6.9 | 2.6 | -2.2 | 0.6 | 9.9 |
| S. Africa | Rand | 18.3 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 19.4 |
| **Developed Markets** | | | | | | |
| UK | Pound | 0.8 | 2.5 | 0.3 | -3.3 | 11.6 |
| Europe | Euro | 0.9 | 2.7 | -1.6 | -4.9 | 6.1 |
| Japan | Yen | 136.2 | 4.7 | -1.3 | -2.0 | 18.4 |
| Switzerland | Franc | 0.9 | 2.8 | -0.4 | -3.6 | 2.8 |
| US | Dollar Index | 104.9 | 2.7 | -1.0 | -3.5 | 8.4 |

नोट: **1. सभी मुद्रा दरें यूएसडी के मुकाबले हैं (यूएसडी इंडेक्स को छोड़कर)**

**2. नकारात्मक संकेत (प्रतिशत बदलाव के आंकड़ों में) आधार मुद्रा (यूएसडी) के मुकाबले भाव मुद्रा की सराहना दर्शाता है।**

स्रोत: **रिफिनिटिव**

**Note:** 1. All Currency rates are against USD (excluding USD Index)

2. Negative sign (in percentage change figures) indicates appreciation of quote currency against the base currency (USD)

**Source:** Refinitiv

**चित्र 2: यूएसडी-आईएनआर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स और एमएससीआई ईएम करेंसी इंडेक्स में उतार-चढ़ाव**

**Figure 2: Movement of the USD-INR Index, US Dollar Index and MSCI EM Currency Index**

टिप्पणी:

**1. सभी सूचकांकों को 31 जनवरी 2022 को 100 पर सामान्य कर दिया गया है।**

**2. यू.एस. डॉलर इंडेक्स विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी के सापेक्ष यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के मूल्य का एक सूचकांक है। सूचकांक ऊपर जाता है जब अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं की तुलना में मूल्य प्राप्त करता है। इंडेक्स को इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज द्वारा बनाए रखा और प्रकाशित किया जाता है। यह निम्नलिखित चुनिंदा मुद्राओं के सापेक्ष डॉलर के मूल्य का भारित ज्यामितीय माध्य है: यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक।**

**3. MSCI इमर्जिंग मार्केट्स (EM) करेंसी इंडेक्स यूएस डॉलर के सापेक्ष पच्चीस इमर्जिंग मार्केट करेंसियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।**

स्रोत: **रिफिनिटिव**

**Note:**

1. All indices have been normalised to 100 on January 31, 2022.
2. The U.S. Dollar Index is an index of the value of the United States Dollar relative to a basket of foreign currencies. The Index goes up when the U.S. Dollar gains value compared to other currencies. The index is maintained and published by Intercontinental Exchange. It is a weighted geometric mean of the dollar's value relative to following select currencies: Euro, Japanese Yen, Pound Sterling, Canadian Dollar, Swedish Krona, Swiss Franc.
3. The MSCI Emerging Markets (EM) Currency Index tracks the performance of twenty five emerging market currencies relative to the US Dollar.

**Source:** Refinitiv

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की विदेशी होल्डिंग्स   * **जनवरी 2023 के अंत में, जापान अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा विदेशी धारक था, जिसके पास कुल जारी अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज का 15 प्रतिशत था, जिसके बाद चीन (12 प्रतिशत) था। जनवरी 2023 के अंत में अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की कुल विदेशी हिस्सेदारी 7,402.5 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें से भारत के पास 232 अरब अमेरिकी डॉलर (3 प्रतिशत) थी और यह ग्यारहवां सबसे बड़ा धारक था। भारत की हिस्सेदारी में 3.5 प्रतिशत (एमओएम) और 16.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।** |  | **Foreign Holdings of US Treasury Securities**   * At the end of January 2023, Japan was the largest foreign holder of US Treasury Securities, holding 15 per cent of the total issued US Treasury Securities, followed by China (12 per cent). The total foreign holding of US Treasury Securities at the end of January 2023 was US$ 7,402.5 billion, of which India held US$ 232 billion (3 per cent) and was the eleventh largest holder. India’s holding increased by 3.5 per cent (M-o-M) and by 16.8 per cent (Y-o-Y). |

**Table 4: Major Foreign Holders of US Treasury Securities (USD billion)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Country** | **Jan-23** | **Change over Period (%)** | |
| **1-Month** | **1-Year** |
| Japan | 1,104.40 | 2.6 | -15.0 |
| China, Mainland | 859.40 | -0.9 | -16.9 |
| United Kingdom | 668.30 | 2.1 | 9.4 |
| Belgium | 331.10 | -6.5 | 36.3 |
| Cayman Islands | 318.20 | -3.4 | 1.7 |
| Luxembourg | 290.50 | 7.7 | -1.7 |
| Switzerland | 285.30 | 0.5 | 4.9 |
| Ireland | 254.10 | 18.1 | 16.8 |
| Brazil | 253.40 | -0.5 | -17.9 |
| Taiwan | 234.60 | 4.0 | -5.1 |
| India | 232.00 | 3.5 | 16.8 |
| France | 226.80 | 2.6 | 0.5 |
| Canada | 214.00 | -1.6 | -9.4 |
| Hong Kong | 187.60 | 2.6 | -2.1 |
| Singapore | 183.90 | -2.7 | -21.0 |
| Saudi Arabia | 111.00 | -7.3 | -7.0 |
| Korea | 105.80 | 2.8 | -14.5 |
| Norway | 104.40 | 13.5 | -9.8 |
| Germany | 91.30 | -9.3 | 8.3 |
| Bermuda | 77.40 | -5.0 | 11.0 |
| Netherlands | 73.70 | 9.3 | 21.6 |
| Australia | 64.90 | 10.8 | 44.5 |
| Mexico | 62.20 | 8.9 | 4.2 |
| Philippines | 58.20 | -0.7 | 31.1 |
| Israel | 52.80 | 14.8 | -15.0 |
| Kuwait | 48.80 | 1.0 | -7.0 |
| United Arab Emirates | 46.10 | -3.6 | -27.7 |
| Sweden | 43.30 | -10.7 | -14.4 |
| Thailand | 41.20 | 1.0 | 76.1 |
| Bahamas | 40.90 | 8.5 | -8.9 |
| Vietnam | 40.30 | 9.2 | 47.1 |
| Iraq | 40.20 | 2.6 | -4.5 |
| Italy | 39.50 | -0.8 | 18.6 |
| Chile | 39.50 | -6.6 | -27.5 |
| Colombia | 38.10 | -17.2 | 6.1 |
| Spain | 36.30 | -1.6 | -14.2 |
| Poland | 34.20 | 0.6 | -3.1 |
| Peru | 31.80 | -0.9 | 9.7 |
| All Other | 437.20 | -0.5 | 6.6 |
| Grand Total | 7,402.50 | 1.1 | -3.3 |
| Of which | | | |
| For. Official | 3,713.90 | 1.0 | -10.1 |
| Treasury Bills | 249.60 | 4.6 | -6.4 |
| T-Bonds & Notes | 3,464.30 | 0.7 | -10.3 |

टिप्पणी:

**1. 15 मार्च, 2022 को प्रकाशित डेटा**

**2. इस तालिका में डेटा मुख्य रूप से यू.एस.-आधारित संरक्षकों और ब्रोकर-डीलरों से एकत्र किए जाते हैं। चूंकि विदेशी हिरासत खातों में रखी गई यू.एस. प्रतिभूतियां वास्तविक मालिकों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं, इसलिए डेटा ट्रेजरी सिक्योरिटीज के व्यक्तिगत देश के स्वामित्व का सटीक लेखा प्रदान नहीं कर सकता है (TIC FAQ #7 यहां देखें: http://www.treasury.gov/ संसाधन-केंद्र/डेटा-चार्ट-केंद्र/टिक/पृष्ठ/ticfaq1.aspx)**

**3. ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल (TIC) रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत रिपोर्ट किए गए यूएस ट्रेजरी मार्केटेबल और नॉन-मार्केटेबल बिल, बॉन्ड और नोट्स की अनुमानित विदेशी होल्डिंग ट्रेजरी बॉन्ड और नोट्स की होल्डिंग पर मासिक डेटा पर आधारित है, जैसा कि TIC फॉर्म SLT, एग्रीगेट पर रिपोर्ट किया गया है। यू.एस. और विदेशी निवासियों द्वारा लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की होल्डिंग और टीआईसी फॉर्म बीएल2 पर, विदेशी निवासियों के लिए ग्राहकों की यू.एस. डॉलर देनदारियों की रिपोर्ट।**

स्रोत**: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग**

**Note**:

1. Data published on March 15, 2022
2. The data in this table are collected primarily from U.S.-based custodians and broker-dealers. Since U.S. securities held in overseas custody accounts may not be attributed to the actual owners, the data may not provide a precise accounting of individual country ownership of Treasury securities (see TIC FAQ #7 at: http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/ticfaq1.aspx)
3. Estimated foreign holdings of U.S. Treasury marketable and non-marketable bills, bonds, and notes reported under the Treasury International Capital (TIC) reporting system are based on monthly data on holdings of Treasury bonds and notes as reported on TIC Form SLT, Aggregate Holdings of Long-Term Securities by U.S. and Foreign Residents and on TIC Form BL2, Report of Customers' U.S. Dollar Liabilities to Foreign Residents.

**Source**: U.S. Department of the Treasury

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभूति बाजार(सिक्यूरिटीज़)में हुई मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ  **प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ)**   1. भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) - आईओएससीओ ने जून 2020 में सेंट्रल काउंटरपार्टी डिफॉल्ट मैनेजमेंट ऑक्शन- इश्यू फॉर कंसीडरेशन पर रिपोर्ट में प्रकाशित सिफारिशों पर पर्याप्त प्रगति की सूचना दी है। प्रगति के निम्नलिखित घटक हैं:    1. नीलामी शब्दावली, प्रारूपों और नीलामी प्रक्रियाओं के परिचालन पहलुओं का मानकीकरण।    2. CCPs के शासन के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के तरीके पर विचार-विमर्श करने के लिए क्लियरिंग सदस्यों, CCPs और अन्य हितधारकों के बीच डिफ़ॉल्ट प्रबंधन समूहों में व्यापारियों का उपयोग और एक नीलामी में ग्राहक भागीदारी का दायरा पर चर्चा की गई है। 2. IOSCO ने नियामक के सिद्धांतों के उच्च स्तर के कार्यान्वयन की सूचना दी है, अर्थात, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जवाबदेही, व्यावसायिकता, स्थिरता, पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन निवेशकों की सुरक्षा के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उचित और कुशल जोखिम सुनिश्चित करने और व्यवस्थित जोखिमों को संबोधित करने के आधार पर आईओएससीओ के 55 सदस्‍य क्षेत्राधिकारों की इसकी समीक्षा। हालांकि, कुछ उभरते बाजारों में नियामक के कर्तव्य को पूरा करने के लिए परिचालन निर्भरता, धन के स्थिर और निरंतर स्रोत की कमी, अपर्याप्त कानूनी सुरक्षा या अपर्याप्त मानव संसाधन जैसी चुनौतियों की सूचना भी दी है।   **बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स**   1. भुगतान और बाजार अवसंरचना पर समिति (सीपीएमआई)- बीआईएस ने बाजार हितधारकों को सीमा पार भुगतान अंतरसंचालनीयता और सीमा पार भुगतान कार्यक्रम के विस्तार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह टास्क फोर्स भुगतान प्रणालियों की पहुंच और संचालन के घंटों के विस्तार और सीमाओं के पार उन्हें जोड़ने पर काम करेगी। 2. बीआईएस ने बताया है कि 2022 की पहली छमाही में सबसे बड़े वैश्विक बैंकों के लिए बेसल III पूंजी अनुपात पूर्व-महामारी के स्तर तक गिर गया है । डिविडेंड पे-आउट रेशियो के रुझान में बढ़त जारी है क्योंकि बैंकों को अब डिविडेंड में प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ता है जो कि महामारी की शुरुआत में शुरू किया गया था। समूह 1 बैंकों के लिए वेटेड औसत शुद्ध स्थिर अनुदान अनुपात (NSFR) घटकर 123.5% हो गया। जून 2022 तक, NSFR नमूने के सभी बैंकों ने एक अनुपात की सूचना दी जो 100% की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है या उससे अधिक है। अंतिम\_ बेसल III न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए, समूह 1 बैंकों की टियर 1 न्यूनतम आवश्यक पूंजी (MRC) पर पूरी तरह से चरणबद्ध अंतिम बेसल III ढांचे का औसत प्रभाव +2.8% है, दिसंबर 2021 के अंत में +2.4% की तुलना में। समूह 1 बैंकों के लिए वेटेड औसत तरलता कवरेज अनुपात (LCR) पूर्व रिपोर्टिंग अवधि से घटकर 138.4% हो गया।   **प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी)**   1. एसईसी ने निजता अधिनियम के नियमों (जिनके माध्यम से संघीय सरकार द्वारा निजी जानकारी के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है) को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है । वर्तमान नियमों में व्यक्ति से संबंधित रिकॉर्डों के उपयोग और उनमें संशोधन के लिए प्रावधान हैं, प्रस्तावित संशोधन कई प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों की भाषा को और स्पष्ट, अद्यतन और सुव्यवस्थित करेगा, व्यक्ति स्वयं से संबंधित जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं इस संबंध में आयोग की प्रक्रिया के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा । यदि अपनाया गया, प्रस्तावित नियम प्रक्रिया और शुल्क संबंधी प्रावधानों को संशोधित करेगा, साथ ही अनावश्यक प्रावधानों को हटा देगा । प्रस्तावित नियम किसी की पहचान को सत्यापित करने और निजता अधिनियम से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के उपयोग की भी अनुमति देगा । 2. एसईसी ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग संगठनों पर रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में रेटिंग निगरानी प्रथाएं, वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्रेडिट रेटिंग पर COVID-19 का प्रभाव, व्यापार संचार प्रथाओं, कर्मचारी द्वारा प्रतिभूति स्वामित्व, चीन में स्थित फर्मों की रेटिंग, ईएसजी उत्पाद का विपणन और स्टैंड के विकास से क्रेडिट रेटिंग का प्रभाव शामिल है। 3. एसईसी व्यापार के बाद दो व्यावसायिक दिनों (टी+2) से एक (टी+1) तक निकासी और निपटान में जोखिम को कम करने के लिए मानक निपटान चक्र को छोटा करने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे रहा है। यह विलंबता को कम करेगा, जोखिम को कम करेगा और दक्षता को बढ़ावा देगा। नियम संस्थागत ट्रेडों के प्रसंस्करण में सुधार करेंगे। ब्रोकर-डीलर को या तो लिखित समझौतों में प्रवेश करने या लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने, बनाए रखने और लागू करने की आवश्यकता होगी, जो तकनीकी रूप से व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द और बाद में व्यापार के अंत से पहले आवंटन, पुष्टिकरण और प्रतिज्ञान को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। तारीख। कुछ प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए आवंटन, पुष्टि और प्रतिज्ञान के रिकॉर्ड बनाने और रखने के लिए पंजीकृत निवेश सलाहकारों की आवश्यकता होगी। अंतिम नियम सीधे-सीधे प्रसंस्करण की सुविधा के लिए एक नई आवश्यकता जोड़ते हैं, जो कुछ प्रकार की समाशोधन एजेंसियों पर लागू होती है जो केंद्रीय मिलान सेवाएं प्रदान करती हैं। अंतिम नियमों के लिए केंद्रीय मिलान सेवा प्रदाताओं को नई नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने, लागू करने, बनाए रखने और लागू करने की आवश्यकता होगी, जो सीधे-सीधे प्रसंस्करण की सुविधा के लिए यथोचित रूप से डिज़ाइन किए गए हैं और उन्हें आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो सीधे के संबंध में प्रगति का वर्णन और मात्रा निर्धारित करती है। - प्रसंस्करण के माध्यम से। . अंतिम नियमों की अनुपालन तिथि 28 मई, 2024 है। 4. अक्टूबर 2019 और मई 2021 के बीच तनाव परीक्षण और समाशोधन निधि पद्धति के लिए SEC द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुपालन में विफलता के लिए SEC ने विकल्प समाशोधन निगम पर $17 मिलियन के जुर्माने के साथ शुल्क लगाया। एसईसी के आदेश में आगे पाया गया कि ओसीसी अपनी व्यापक तनाव परीक्षण प्रणाली को संशोधित करने में विफल रही और इस विफलता के एसईसी को समय पर अधिसूचना प्रदान नहीं की, जैसा कि विनियमन एससीआई द्वारा आवश्यक है। विनियमन SCI के लिए कुछ संस्थाओं को सिस्टम व्यवधान, सिस्टम अनुपालन मुद्दों और सिस्टम घुसपैठ के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं के आयोग को सूचित करने की आवश्यकता होती है। एसईसी के आदेश में यह भी पाया गया है कि ओसीसी अपनी मार्जिन पद्धति, मार्जिन नीति, और विशिष्ट गलत तरीके के जोखिम और हॉलिडे मार्जिन से संबंधित तनाव परीक्षण और समाशोधन निधि पद्धति का पालन करने में विफल रही है। उपचारात्मक प्रयास में इसकी मॉडल सत्यापन नीतियों और प्रक्रियाओं का संशोधन, इसके जोखिम डेटा शासन में वृद्धि, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों सहित इसके नियंत्रण वातावरण के तत्व के कार्यान्वयन शुल्क शामिल हैं; और परिवर्तनों पर उचित प्रशिक्षण आयोजित करें। 5. एसईसी पंजीकृत निवेश सलाहकारों द्वारा प्रबंधित ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह रिकॉर्ड-कीपिंग और रिपोर्टिंग दायित्वों से संबंधित नियमों में संशोधन करेगा। प्रस्तावित नियम डोड-फ्रैंक अधिनियम की धारा 411 के तहत आयोग के अधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें निवेश सलाहकार के कब्जे में किसी भी ग्राहक संपत्ति को शामिल करने के लिए क्लाइंट फंड और प्रतिभूतियों से परे वर्तमान निवेश सलाहकार हिरासत नियम के आवेदन को व्यापक बनाया जाएगा या जब एक निवेश सलाहकार के पास अधिकार होगा ग्राहक संपत्ति का कब्जा प्राप्त करें। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि सलाहकार ग्राहक की संपत्ति को बनाए रखते समय योग्य संरक्षक कुछ मानक हिरासत सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन सुरक्षाओं को अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि योग्य अभिरक्षक दिवालियापन या अन्य दिवालिया होने की स्थिति में संपत्ति की सुरक्षा के लिए ग्राहक की संपत्तियों को ठीक से अलग किया जाए और खातों में रखा जाए। प्रस्तावित नियम कुछ प्रतिभूतियों और भौतिक संपत्तियों के लिए सुरक्षा को भी बढ़ाएगा जिन्हें योग्य संरक्षक द्वारा बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव ग्राहक की संपत्ति को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र सार्वजनिक लेखाकार से एक आश्चर्यजनक परीक्षा प्राप्त करने के लिए ग्राहक संपत्ति की हिरासत के साथ एक सलाहकार के लिए वर्तमान आवश्यकता को बरकरार रखता है, लेकिन यह इसके उपयोग की उपलब्धता का विस्तार करने, निवेशक सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑडिट प्रावधान को संशोधित करेगा, और अनुपालन की सुविधा।   **सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस)**   1. एमएएस के ग्रीन फाइनेंस इंडस्ट्री टास्कफोर्स ने सिंगापुर स्थित वित्तीय संस्थानों के लिए ग्रीन और ट्रांजिशन टैक्सोनॉमी पर अपना अंतिम सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। इस परामर्श ने निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में हरित और संक्रमण गतिविधियों के वर्गीकरण के लिए विस्तृत सीमा और मानदंड पर इनपुट मांगा है;- कृषि और वानिकी/भूमि उपयोग, औद्योगिक; अपशिष्ट और पानी; सूचना व संचार तकनीक; और कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन। इस सार्वजनिक परामर्श के उल्लेखनीय प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र के लिए "उपाय-आधारित दृष्टिकोण" और "डू नो सिग्निफिकेंट हार्म (डीएनएसएच)" को अपनाना है। ये प्रस्ताव उत्सर्जन में कमी के उपायों को अपनाने और अन्य पर्यावरणीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को समाप्त करने का इरादा रखते हैं। जनवरी 2021 और मई 2022 में कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए आयोजित इसी तरह के परामर्शों की श्रृंखला में यह तीसरा परामर्श है। 2. सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सिंगापुर के PayNow और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के बीच लिंकेज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सिंगापुर और भारत में भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों जैसे डीबीएस, लिक्विड ग्रुप, एक्सिस बैंक, डीबीएस इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना है। लॉन्च की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधान मंत्री ली सीन लूंग ने की थी। यह उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में दोनों देशों के बैंक खातों या ई-वॉलेट के बीच धन भेजने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। वे केवल मोबाइल फोन नंबर, यूपीआई पहचान या वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। 3. सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने कॉर्पोरेट वित्त (सीएफ) सलाहकारों के लिए उचित परिश्रम और आचरण आवश्यकताओं के अनिवार्य आधारभूत मानकों को लागू करने का नोटिस जारी किया है। इन मानकों के लिए अब सीएफ सलाहकारों को अनिवार्य न्यूनतम मानकों का पालन करने की आवश्यकता होगी, जबकि पृष्ठभूमि की जांच और प्रासंगिक हितधारकों के साथ साक्षात्कार सहित सीएफ लेनदेन पर उचित परिश्रम करना होगा। इन आवश्यकताओं को कॉर्पोरेट वित्त सलाहकारों के लिए व्यावसायिक आचरण आवश्यकताओं पर नोटिस में निर्धारित किया गया है। एमएएस ने सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखा है|   **वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए)**   1. एफसीए अपने एसेट मैनेजमेंट रेगुलेशन को अपडेट करने के बारे में राय मांग रहा है। फ्यूचर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एफसीए को यूके के बाजारों और उपभोक्ताओं की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए संपत्ति प्रबंधन विनियमन में सुधार करने में सक्षम बनाता है। तकनीकी विकास और नवाचार को सक्षम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव किए जाएंगे। फिलहाल कोई प्रस्ताव तय नहीं है, इसके बजाय लक्ष्य आगे विचार-विमर्श को बढ़ाना और हितधारकों के विचारों को सुनना है। 2. फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने फर्मों को 2022 के दौरान 8,582 प्रमोशन में संशोधन करने या हटाने के लिए कहा – जो कि 2021 से 14 गुना अधिक था। इसने बिग टेक कंपनियों को केवल उन प्रमोशन की अनुमति देने के लिए कहा है जिन्हें FCA द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि टेक कंपनियों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। इसने समस्या फर्मों और भ्रामक विज्ञापनों को खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरणों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अनधिकृत व्यक्तियों (फिन-फ्लुएंसर) को पहले से ही कुछ निवेशों के गुणों के बारे में लोगों को सलाह देने से मना कर दिया गया है, अन्यथा इससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 3. फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) डेट पैकेजर फर्मों को डेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स से रेफरल फीस प्राप्त करने से प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है। अनुपयुक्त या खराब सलाह वास्तव में लोगों के वित्तीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए एफसीए ग्राहक के सर्वोत्तम हित एवं फर्मों की आमदनी के बीच हितों के टकराव को दूर करने की योजना बना रहा है । एक गलत ऋण समाधान, जैसे कि - एक व्यक्तिगत स्वैच्छिक व्यवस्था या संरक्षित ट्रस्ट डीड, के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा, इसने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे अनधिकृत ऋण समाधान प्रदाता को एफसीए द्वारा अधिकृत करने की आवश्यकता हो सकती है। |  | **HIGHLIGHTS OF DEVELOPMENTS IN**  **INTERNATIONAL SECURITIES MARKET**  **International Organisation of Securities Commission (IOSCO)**   1. Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) - IOSCO has reported substantial progress has been made on recommendations published in Report on Central counterparty default management auction- Issues for Consideration in June 2020. The progress has following components:  * Standardisation of auction terminology, formats and operational aspects of auction procedures. * Discussions among Clearing Members, CCPs and other stakeholders have been made to deliberate on the way forward in areas of governance of CCPs Default management process, use of traders in default management groups and the scope of client participation an auction.  1. IOSCO has reported high level of implementation of the regulator's principles, i.e., independence, objectivity, accountability, professionalism, consistency, adequate powers and resources to deliver the core objectives of protecting investors, ensuring fair and efficient risk and addressing systematic risks based on its review of 55 IOSCO member jurisdictions. However, gaps like operational dependence, lack of stable and continuous source of funding, inadequate legal protection or inadequate human resource to carry out Regulator's duty has been reported in some emerging markets.   **Bank of Internatonal Settlements**   * + - 1. Committee on Payments and Market infrastructure (CPMI)- BIS has invited market stakeholders to join cross-border payments interoperability and extension to the cross-border payments programme. The task force will work on the extension of the access to and operating hours of payment systems and their linking across borders.       2. BIS has reported that the Basel III capital ratios for largest global banks fell to pre- pandemic levels in H1 2022. The dividend pay-out ratio continues its upward trends as banks no longer face restriction in dividends that were introduced on the onset of the pandemic period. The weighted average Net Stable Funding Ratio (NSFR) decreased to 123.5% for Group 1 banks. As of June 2022, all banks in the NSFR sample reported a ratio that met or exceeded the minimum requirement of 100%. The implementation of the \_final\_ Basel III minimum requirements began on 1 January 2023. For this reporting period, the average impact of the fully phased-in final Basel III framework on the Tier 1 minimum required capital (MRC) of Group 1 banks is +2.8%, compared with +2.4% at end-December 2021. The weighted average Liquidity Coverage Ratio (LCR) decreased from the prior reporting period to 138.4% for Group 1 banks.   **Securities and Exchange Commission**  1. SEC proposes the revisions to the Privacy Act rules which governs the handling of personal information in federal government. The current rules make provision for access and amendment of records pertaining to the individual. The revision will clarify, update and streamline the language of several procedural provisions providing greater clarity regarding the Commission’s process for how individuals can access information pertaining to themselves. If adopted, the proposed rule would revise procedural and fee provisions, as well as eliminate unnecessary provisions. The proposed rule would also allow for electronic methods to verify one’s identity and to submit Privacy Act requests.  2. SEC published report on nationally recognised Statistical Rating Organisations. The report contains the rating surveillance practices, impact of COVID-19 on commercial real estate credit ratings, business communication practices, securities ownership by the employee, rating of firms based in China, the effect of credit ratings from the marketing and development of stand-alone ESG products.  3. SEC finalizes the rules to shorten the standard settlement cycle from two business days after trade (T+2) to one (T+1) reducing risks in clearance and settlement. It would reduce latency, lowers risk and promotes efficiency. The rules will improve the processing of institutional trades. It will require a broker-dealer to either enter into written agreements or establish, maintain, and enforce written policies and procedures reasonably designed to ensure the completion of allocations, confirmations, and affirmations as soon as technologically practicable and no later than the end of trade date. It will require registered investment advisers to make and keep records of the allocations, confirmations, and affirmations for certain securities transactions. The final rules add a new requirement to facilitate straight-through processing, which applies to certain types of clearing agencies that provide central matching services. The final rules will require central matching service providers to establish, implement, maintain, and enforce new policies and procedures reasonably designed to facilitate straight-through processing and require them to submit an annual report to the Commission that describes and quantifies progress with respect to straight-through processing. The compliance date for the final rules is May 28, 2024.  4. SEC charges Options Clearing Corporation with failure of compliance with SEC approved rules for stress testing and clearing fund methodology between October 2019 and may 2021 with the penalty of $17 millions. The SEC’s order further finds that OCC failed to modify its Comprehensive Stress Testing System and did not provide timely notification to the SEC of this failure as required by Regulation SCI. Regulation SCI requires certain entities to take corrective action with respect to systems disruptions, systems compliance issues, and systems intrusions and to notify the Commission of such events. The SEC’s order also finds that OCC failed to comply with its margin methodology, margin policy, and stress testing and clearing fund methodology relating to specific wrong way risk and holiday margin. The remedial effort includes the revision of its model validation policies and procedures, enhancement of its risk data governance, implementation charges to element of of its control environment including processes, procedures, and controls; and conduct appropriate training on the changes.  5. SEC proposes rule changes to enhance protections of customer assets managed by registered investment advisers. It would amend rules related to record- keeping and reporting obligations. The proposed rules would exercise Commission authority under section 411 of the Dodd-Frank Act by broadening the application of the current investment adviser custody rule beyond client funds and securities to include any client assets in an investment adviser’s possession or when an investment adviser has authority to obtain possession of client assets. The proposed changes are intended to help ensure that qualified custodians provide certain standard custodial protections when maintaining an advisory client’s assets. These protections are designed, among other things, to ensure client assets are properly segregated and held in accounts to protect the assets in the event of a qualified custodian bankruptcy or other insolvency. The proposed rule would also enhance protections for certain securities and physical assets that cannot be maintained by a qualified custodian. Additionally, the proposal retains the current requirement for an adviser with custody of client assets to obtain a surprise examination from an independent public accountant to verify client assets, but it would modify the audit provision to expand the availability of its use, enhance investor protection, and facilitate compliance.  **Monetary Authority of Singapore**  1. The Green Finance Industry Taskforce of MAS has launched its final public consultation on a green and transition taxonomy for Singapore-based financial institutions. This consultation sought input on the detailed threshold and criteria for the classification of green and transition activities in the following five sectors, namely; agriculture and forestry/land use, industrial; waste and water; information and communications technology; and carbon capture and sequestration. The noteworthy proposals of this public consultation are adoption of a “measures –based approach” for the industrial sector and “Do No Significant Harm (DNSH)”. These proposals intent to adopt a range of emissions reduction measures and elimination of activities causing adverse impact on the other environmental objectives. This is a third consultation in a series of such similar rounds of consultations held in January 2021 and May 2022 for some other sectors.  2. The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Reserve Bank of India (RBI) launched the linkage between Singapore’s PayNow and India’s Unified Payments Interface (UPI). The object of this to facilitate customers of participating financial institutions in Singapore and India such as DBS, Liquid Group, Axis Bank, DBS India, ICICI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank and State Bank of India. The launch was officiated by Prime Minister of India, Narendra Modi and Prime Minister of Singapore, Lee Hsien Loong. This will enable users to send and receive funds between bank accounts or e-wallets across the two countries in real-time. They can do this using just the mobile phone number, UPI identity, or Virtual Payment Address.  3. The Monetary Authority of Singapore (MAS) has issued a notice of imposing mandatory baseline standards of due diligence and conduct requirements for corporate finance (CF) advisers. These standards will now require from CF advisers to adhere mandatory minimum standards while conducting due diligence on CF transactions including background checks and interviews with relevant stakeholders. These requirements are set out in the Notice on Business Conduct Requirements for Corporate Finance Advisers. MAS has taken into account feedback received from the public consultation.    **Financial Conduct Authority**  1. FCA is looking for views on updating its asset management regulation. The Future Regulatory Framework enables FCA to improve asset management regulation meeting the contemporary needs of the UK markets and consumers. The changes will be done staying in tune with international standards to and enable technological development and innovation. No proposal is fixed, as of now, instead the goal is to enhance further deliberations and listen to stakeholder’s views.  2. The Financial Conduct Authority (FCA) asked firms to amend or remove 8,582 promotions during 2022 - 14 times more than 2021. It has nudged Big Tech companies to only permit those promotions that have been approved by FCA. Though more actions need to be taken by tech companies to protect consumers. It has made significant improvements to the digital tools it uses to find problem firms and misleading adverts. Unauthorised individuals (Fin-fluencers) are already forbid to advise people on the merits of certain investments, otherwise it could lead to action being taken against them.  3. The Financial Conduct Authority (FCA) is planning to ban debt packager firms from receiving referral fees from debt solution providers. Unsuitable or poor advice can really harm people’s financial lives, therefore FCA is planning to remove the conflict of interest between firms giving advice in the customer’s best interest and recommending an option that makes firms more money. A wrong debt solution, such as an Individual Voluntary Arrangement or Protected Trust Deed, can cause dire consequences. Further, it also clarified how unauthorised debt solution provider, may need to be authorised by the FCA. |
| भारतीय प्रतिभूति बाजार के संबंध में उठाए गए नीतिगत कदम   1. **कैश और डेरिवेटिव खंड में ग्राहकों से मार्जिन के अग्रिम संग्रह के सत्यापन को सक्षम करने के लिए ढांचे में परिवर्तन**   सेबी ने कैश और डेरिवेटिव खंड में ग्राहकों से मार्जिन के अग्रिम संग्रह के सत्यापन को सक्षम करने के लिए एक ढांचा निर्धारित किया है। समय-समय पर सेबी ने बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार ढांचे में बदलाव किया है। हाल ही में बाजार सहभागियों के प्रतिनिधित्व और विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर सेबी ने ढांचे मे एक बदलाव किया है, जिसके अनुसार डेरिवेटिव खंड में ग्राहकों से दिन के अंत (ईओडी) मार्जिन संग्रह की गणना निश्चित दिन की शुरुआत (बीओडी) के आधार पर की जाएगी। |  | **POLICY DEVELOPMENTS IN INDIAN SECURITIES MARKET**   1. **Changes to the Framework to Enable Verification of Upfront Collection of Margins from Clients in Cash and Derivatives segments**   SEBI has prescribed framework to enable verification of upfront collection of margins from clients in cash and derivatives segment. From time to time SEBI has changed the framework as per market requirements. Recently after representations from market participants and base on deliberations with various stakeholders SEBI changed the framework that the End of Day (EOD) margin collections from clients in derivative segment shall be calculated based on the fixed Beginning of Day (BOD) margin parameters. |
| *Source: SEBI/HO/MRD/MRD-PoD-2/P/CIR/2023/016 dated February 01, 2023* | | |
| 1. **वैकल्पिक निवेश कोष (ए आई एफ) कॉर्पोरेट बॉन्ड में खरीदारी अब रिक्वैस्ट फॉर क्वोट (आर ऑफ़ क्यू) मंच के माध्यम से करेंगे**   स्टॉक एक्सचेंजों के आर ऑफ़ क्यू प्लेटफॉर्म पर तरलता बढ़ाने और कॉर्पोरेट बॉन्ड के सेकेंडरी मार्केट में व्यापार से संबंधित पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ाने के लिए, सेबी ने म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा आर ऑफ़ क्यू मंच पर खरीदारी के लिए शर्तें निर्धारित की थीं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और सेबी की वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति (ए आई पीए सी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित किया जाता है कि ए आई एफ एक महीने में कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने कुल द्वितीयक बाजार व्यापारों का कम से कम 10% आर एफ क्यू मंच पर करेंगे। |  | 1. **Transaction in Corporate Bonds through Request for Quote (RFQ) platform by Alternative Investment Funds (AIFs)**   To increase liquidity on RFQ platform of stock exchanges and to enhance transparency and disclosure pertaining to trading in secondary market in Corporate Bonds, SEBI had prescribed stipulations for transactions on RFQ platform by Mutual Funds, Portfolio Management Services and Stock Brokers. Considering the above and taking into account the recommendations of the Alternative Investment Policy Advisory Committee(AIPAC) of SEBI, it is stipulated that AIFs shall undertake at least 10% of their total secondary market trades in Corporate Bonds by value in a month by placing/seeking quotes on the RFQ platform. |
| *Source: SEBI/HO/AFD/PoD/P/CIR/2023/017 dated February 01, 2023* | | |
| 1. **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए परिचालन परिपत्र में संशोधन**   जनवरी 2023 में, सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक परिचालन परिपत्र जारी किया था जो एक ही स्थान पर सभी मौजूदा परिपत्रो का संकलन था। फरवरी 03, 2023 में परिचालन परिपत्र में कई बदलाव किए गए, जहां कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया, वही कुछ को हटा दिया गया और कुछ नए प्रावधान लाये गए। |  | 1. **Amendments to Operational Circular for Credit Rating Agencies**   In January 2023, SEBI had released an operational circular for Credit Rating agencies which was a compilation of all existing circulars at one place. In February 03, 2023 several changes were made to the operational circular where, certain provisions were modified, some were deleted and some new insertions were also made |
| *Source: SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD2/P/CIR/2023/19 dated February 03, 2023* | | |
| 1. **न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (ऍम पी एस) प्राप्त करने का तरीका**   फरवरी 2018 में, सेबी एक परिपत्र लेकर आया जिसमें अलग-अलग तरीके थे जिनका उपयोग सूचीबद्ध संस्थाएँ न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (ऍम पी एस) प्राप्त करने के लिए कर सकते है । यह सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियम) नियम, 1957 और सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के अंतर्गत अनिवार्य है । विनियमन को शिथिल करने और ऍम पी एस अनुपालन प्राप्त करने के लिए नए तरीकों को जोड़ने के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं और अन्य हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, सेबी ने हाल के एक परिपत्र में समीक्षा की और मौजूदा तरीकों में से कुछ को विचारशील बनाया और सूचीबद्ध संस्थाओं को ऍम पी एस अनुपालन प्राप्त करने की सुविधा के लिए दो नए तरीके जोड़े। स्टॉक एक्सचेंज ऍम पी एस मानदंडों का अनुपालन क`रने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं की निगरानी करेगा, गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, तो तिमाही आधार पर सेबी को सूचित किया जाएगा। |  | 1. **Manner of achieving minimum public shareholding**   In February 2018, SEBI came up with a circular that had different methods that listed entities may use to achieve compliance with the minimum public shareholding (MPS) requirements mandated under Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 (SCRR) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). Upon receipt of representations from listed entities and other stakeholders to relax the regulation and to add newer methods to achieve MPS compliance, SEBI in a recent circular reviewed and rationalized few of the existing methods and added two new methods to facilitate listed entities achieve MPS compliance. The Stock Exchange(s) shall monitor the listed entities complying with MPS norms, Non-compliance if any, shall be reported to SEBI on a quarterly basis. |
| *Source: SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/18 dated February 03, 2023* | | |
| 1. **ग्रीनवाशिंग की घटनाओं से बचने के लिए ग्रीन डेट सिक्योरिटीज (हरित ऋण प्रतिभूति) से संबंधित क्या करें और क्या न करें**   सेबी (ऐन सी एस) विनियम 2021, "हरित ऋण प्रतिभूति” की परिभाषा देती है एवं 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया परिचालन परिपत्र हरित ऋण प्रतिभूति जारी करने/ जारी करने का प्रस्ताव करने वाली संस्थाओं के लिए प्रारंभिक और निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं को प्रदान करती है। हरित ऋण प्रतिभूति के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की गई और परिणामी बदलाव किए गए । किए गए परिवर्तन ग्रीनवाशिंग के संबंध में बाजार सहभागियों की चिंता को संबोधित करते हैं और जारीकर्ता इसे होने से रोकने के लिए प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे |  | 1. **Dos and don’ts relating to green debt securities to avoid occurrences of greenwashing**   SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (NCS Regulations) defines “green debt security” and Operational circular for issue and listing of Non-Convertible Securities (NCS), Securitised Debt Instruments (SDI), Security Receipts (SR), Municipal Debt Securities and Commercial Paper (CP) dated August 10, 2021 provides the initial and continuous disclosure requirements for entities issuing/ proposing to issue green debt securities. The extant framework of ‘green debt security was reviewed and consequential changes were made. The changes made addresses concern of market participants, regarding greenwashing and issuers shall follow the guidelines provided to avoid its occurrence. |
| *Source: SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/020 dated February 03, 2023* | | |
| 1. **ग्रीन डेट सिक्योरिटीज (हरित ऋण प्रतिभूति) जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए संशोधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं**   सेबी के एन सी एस परिचालन परिपत्र का अध्याय IX हरित ऋण प्रतिभूति जारी करते समय पालन करने के लिए मानदंडों को निर्दिष्ट करता है । भारत के साथ-साथ दुनिया भर में सस्टेनेबल फाइनेंस में बढ़ती रुचि की पृष्ठभूमि में, और आई औ स को द्वारा मान्यता प्राप्त अद्यतन ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के साथ हरित ऋण प्रतिभूति के मौजूदा ढांचे को संरेखित करने की दृष्टि से, सेबी ने हरित ऋण प्रतिभूतियों के लिए विनियामक ढाँचे की समीक्षा की। तदनुसार, एन सी एस परिचालन परिपत्र के अध्याय IX को पूरी तरह से एक नए अध्याय के साथ बदल दिया गया। |  | 1. **Revised Disclosure Requirements for Issuance and Listing of Green Debt Securities**   Chapter IX of SEBI’s NCS Operational Circular specifies norms to follow while issuing green debt securities. In the backdrop of increasing interest in sustainable finance in India as well as around the globe, and with a view to align the extant framework for green debt securities with the updated Green Bond Principles (GBP) recognised by IOSCO, SEBI undertook a review of the regulatory framework for green debt securities. Accordingly, Chapter IX of NCS Operational Circular was entirely replaced with a fresh new chapter |
| *Source: SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/023 dated February 06, 202* | | |
| 1. **क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकरों (क्यू एस बी) पर बढ़े हुए दायित्व और जिम्मेदारियां**   कुछ स्टॉक ब्रोकर्स अपने आकार, ट्रेडिंग वॉल्यूम और उनके द्वारा सौंपे गए ग्राहकों के फंड की राशि के कारण भारतीय प्रतिभूति बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर आ गए हैं। ऐसे स्टॉक ब्रोकरों की विफलता से बड़ी संख्या में निवेशकों की सेवाओं में बाधा उत्पन्न होगी और प्रतिभूति बाजार में इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। इसलिए ऐसे स्टॉक ब्रोकरों से संबंधित अनुपालन और निगरानी आवश्यकताओं को और मजबूत करने और प्रतिभूति बाजार के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्टॉक ब्रोकरों को उनके आकार और संचालन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स (क्यू एस बी) के रूप में नामित किया जाएगा। सेबी के परिपत्र में उन मापदंडों का विवरण दिया गया है, जिन के आधार पर स्टॉक ब्रोकर को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में नामित करने के लिए विचार किया जाएगा, और साथ ही मे उनके बढ़े हुए दायित्वों और जिम्मेदारियों और क्यू एस बी की बढ़ी हुई निगरानी पर दिशानिर्देश मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों द्वारा किए जाएंगे |  | 1. **Enhanced obligations and responsibilities on Qualified Stock Brokers (QSBs)**   Certain stock brokers due to their size, trading volumes and amount of clients’ fund handed by them have come to occupy a significant position in Indian securities market. Failure of such stock brokers will cause disruption in services to large number of investors and may have a widespread impact in the securities market. Hence to further strengthen the compliance and monitoring requirements relating to such stock brokers and to ensure efficient functioning of securities market, certain stock brokers having regard to their size and scale of operations will be designated as Qualified Stock Brokers (QSB). SEBI’s circular details the parameters which shall be considered for designating a stock broker as QSB, enhanced obligations and responsibilities and guidelines on enhanced monitoring of QSBs which shall be carried out by Market Infrastructure Institutions. (MII). |
| *Source: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/24 dated February 06, 2023* | | |
| 1. **सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) विनियम, 1992 के तहत स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता (ओबीपीपी) के रूप में परिचालन करने/संचालन करने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं को समय का विस्तार प्रदान करना**   सेबी के नियमों की आवश्यकता है कि ओबीपीपी के रूप में कार्य करने वाली इकाई को पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। संस्थाओं को आवेदन करने और खुद को पंजीकृत कराने के लिए 09 नवंबर, 2022 से तीन महीने की मोहलत दी गई थी। इसके अलावा सेबी ने ओबीपीपी के रूप में परिचालन करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए भारत में निगमित कंपनी होना अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (एमसीए) का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके लिए एमसीए ने पंद्रह दिन का समय दिया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सेबी ने सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) विनियम, 1992 के तहत स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए 09 फरवरी, 2023 से शुरू होने वाली तीन सप्ताह की अतिरिक्त समय अवधि देने का निर्णय लिया है। |  | 1. **Grant of extension of time to entities operating/ desirous of operating as Online Bond Platform Providers (OBPPs) for making an application to obtain certificate of registration as a stock broker under the SEBI (Stock Brokers) Regulations, 1992**   SEBI regulations require that an entity acting as an OBPPs needs a certificate of registration. Entities were given a grace period of three months from November 09, 2022 to apply and get themselves registered. Further SEBI made it mandatory for entities desirous of operating as OBPPs to be companies incorporated in India. The electronic portal of Ministry of Corporate Affairs (MCA) for registration was not working properly for which MCA gave an extension of fifteen days. Considering the above, SEBI has decided to grant additional time period of three weeks commencing from February 09, 2023 for making an application to obtain certificate of registration as a stock broker under the SEBI (Stock Brokers) Regulations, 1992 |
| *Source: SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/025 dated February 07, 2023* | | |
| 1. **संस्थाओं को उप-केयूए के रूप में प्रतिभूति बाजार में यूआईडीएआई की ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गयी**   सेबी ने नवंबर 2019 में निवासी निवेशकों के लिए प्रतिभूति बाजार में संस्थाओं द्वारा पी एम एल ए, 2002 के तहत ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का विवरण देते हुए एक परिपत्र जारी किया था। इसके बाद, सेबी सूचीबद्ध संस्थाएं जो प्रतिभूति बाजार में केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) के रूप में यूआईडीएआई की आधार प्रमाणीकरण सेवा शुरू कर सकती हैं । केयूए सेबी पंजीकृत बिचौलियों को केवाईसी के उद्देश्य से उप-केयूए के रूप में अपने ग्राहकों का आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देगा। समय-समय पर, वित्त मंत्रालय पी एम एल ए के तहत यूआईडीएआई की आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने के लिए संस्थाओं को सूचित करता रहता है। सेबी ने इन संस्थाओं को एक केयूए के साथ एक समझौते में प्रवेश करने और यूआईडीएआई के साथ उप-केयूए के रूप में पंजीकृत होने के लिए अनिवार्य किया है। |  | 1. **Entities allowed to use e-KYC Aadhaar Authentication services of UIDAI in Securities Market as sub-KUA**   SEBI had issued a circular in November 2019 detailing e-KYC authentication facility under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) by entities in the securities market for Resident Investors. Subsequently, SEBI listed entities that can undertake Aadhaar Authentication service of UIDAI as KYC user agency (KUA) in securities market. The KUA shall allow SEBI registered intermediaries to undertake Aadhaar Authentication of their clients as sub-KUA for the purpose of KYC. From time to time, Ministry of Finance keeps notifying entities to use Aadhaar authentication services of UIDAI under PMLA. SEBI has mandated these entities to enter into an agreement with a KUA and get registered with UIDAI as sub-KUAs |
| *Source: SEBI/HO/MIRSD/SEC-5/P/CIR/2023/0026 dated February 08, 2023* | | |
| 1. **स्पष्टीकरण - सेबी (निर्गम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2021 के अध्याय V के तहत स्थायी ऋण उपकरणों, सतत गैर-संचयी वरीयता शेयरों और इसी तरह के उपकरणों को जारी करना और सूचीबद्ध करना**   सेबी एनसीएस विनियम 2021 और उसके तहत जारी किए गए परिपत्र, गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। एनसीएस विनियमों का अध्याय V, सतत ऋण उपकरणों, सतत गैर-संचयी वरीयता शेयरों और इसी तरह के उपकरणों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए शर्तों को निर्धारित करता है। इसके अलावा, यह परिभाषित करता है कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट और परपेचुअल नॉन-क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या हैं। विभिन्न बाजार सहभागियों ने एनसीएस विनियमों के अध्याय V के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता मांगी है, जिसमें एक निश्चित परिपक्वता के लिए प्रतिभूति जारी करने का प्रस्ताव है और जिसमें इक्विटी, राइट-ऑफ आदि में रूपांतरण का विकल्प की विशेषताएं नहीं होंगी। सेबी एक स्पष्टीकरण के साथ आया और एनसीएस विनियमों के अध्याय V के तहत निर्दिष्ट जारी करने और सूचीबद्ध करने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। |  | 1. **Clarification w.r.t. issuance and listing of perpetual debt instruments, perpetual non-cumulative preference shares and similar instruments under Chapter V of the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021**   SEBI (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021 (NCS Regulations) and circulars issued thereunder, provide framework for issuance and listing of non-convertible securities. Chapter V of NCS Regulations, prescribes the conditions for issuance and listing of perpetual debt instruments, perpetual non-cumulative preference shares and similar instruments. Also, it defines what are Perpetual debt instrument and Perpetual non-cumulative preference share. Various market participants have sought clarity on the applicability of the provisions of Chapter V of NCS Regulations, wherein the security is proposed to be issued for a fixed maturity and which shall not have features viz. option of conversion to equity, write-off, etc. SEBI came up with a clarification and mentioned provisions for issuance and listing as specified under Chapter V of the NCS Regulations |
| *Source: SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/027 dated February 08, 2023* | | |
| 1. **सेबी (निर्गम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2021 के विनियम 23(6) के तहत ऋण प्रतिभूतियों के पहली बार जारीकर्ताओं द्वारा अनुपालन के संबंध में स्पष्टीकरण**   सेबी एन सी एस विनियम 2021 के तहत लिए जारीकर्ता जो की एक कम्पनी हो, के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन ("ए ओ ए") में प्रावधान हो जो बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर को सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के संदर्भ में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए आवश्यकता है। मौजूदा ऋण सूचीबद्ध जारीकर्ताओं को अपने एओए में संशोधन करने के लिए विनियम 30 सितंबर, 2023 तक की समयावधि प्रदान करता है। पहली बार जारीकर्ताओं ने सेबी से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने एओए में संशोधन के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से कहा है कि वे पहली बार जारीकर्ताओं से उनकी डेट लिस्टिंग के छह महीने के भीतर अपने एओए में संशोधन करने के लिए एक अंडरटेकिंग लें। |  | 1. **Clarification in respect of the compliance by the first-time issuers of debt securities under SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 with Regulation 23(6)**   SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (“NCS Regulations”) requires the Articles of Association (“AoA”) of issuer that is a company to include provisions with respect to requirement for the board of directors to appoint such person nominated by the debenture trustee in terms of SEBI (Debenture Trustees) Regulations, 1993. The regulation also provides a time period up to September 30, 2023 for existing debt listed issuers to amend their AoA. First time issuers have requested to SEBI to provide them a time frame to amend their AOA. In view of the above, SEBI has asked Stock Exchanges to take an undertaking from first-time issuers to amend their AoA within six months of their debt listing. |
| *Source: SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/028 dated February 09, 2023* | | |
| 1. **इश्यू समरी डॉक्यूमेंट (आईएसडी) का परिचय और इश्यू विज्ञापनों का प्रसार**   सेबी एस ए एस टी विनियम 2011 और सेबी डीलिस्टिंग विनियम के तहत हितधारकों और बाजार सहभागियों द्वारा पब्लिक इशू, फरदर इशू, बायबैक तहत डेटा की खपत को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी में संरचित तरीके से प्रासंगिक जानकारी/डेटा बिंदु उपलब्ध कराए जाएं। तदनुसार, हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, एक इश्यू समरी डॉक्यूमेंट (आईएसडी) तैयार किया गया है। सेबी द्वारा निर्धारित एक्स बी आर एल (एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज) प्रारूप में आईएसडी पेश करने का निर्णय लिया गया है। |  | 1. **Introduction of Issue Summary Document (ISD) and dissemination of issue advertisements**   In order to facilitate consumption of data by stakeholders and market participants, in respect of public issues, further issues, buyback, offers under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SAST Regulations) and SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (Delisting Regulations), etc., it has been decided to make available relevant information / data points at the Stock Exchanges and Depositories in a structured manner. Accordingly, after consultation with the stakeholders, an Issue Summary Document (ISD) has been designed. It has been decided to introduce the ISD in XBRL (Extensible Business Reporting Language) format as prescribed by SEBI |
| *Source: SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/29 dated February 15, 2023* | | |
| 1. **स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा वेबसाइट का रखरखाव**   सेबी ने, विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, स्टॉक ब्रोकर्स (एस-बी)/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डी-पी) द्वारा अपनी संबंधित वेबसाइटों पर कुछ सूचनाओं को प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है। एक नामित वेबसाइट पारदर्शिता लाती है और निवेशकों को एस-बी /डी-पी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अच्छी तरह से सूचित रखने में मदद करती है। उसी के मद्देनजर, प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेशकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, सभी एस-बी और डी-पी को एक निर्दिष्ट वेबसाइट बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है। ऐसी वेबसाइट अनिवार्य रूप से समय-समय पर सेबी/ स्टॉक एक्सचेंजों/ डिपॉजिटरी द्वारा अनिवार्य सूचना प्रदर्शित करेगी। |  | 1. **Maintenance of a website by stock brokers and depository participants**   SEBI, through various circulars, has mandated certain information to be published by Stock Brokers(SB)/ Depository Participants(DP) on their respective websites. A designated website brings in transparency and helps the investors to keep themselves well informed about the various activities of the SB/DP. In view of the same, considering the advancement in technology and need to provide better services to the investors, all SBs and DPs are hereby, mandated to maintain a designated website. Such website shall mandatorily display information mandated by SEBI/Stock Exchanges/Depositories from time to time. |
| *Source: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/30 dated February 15, 2023* | | |
| 1. **साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में सेबी विनियमित संस्थाओं (आरईएस) के लिए सलाह**   वित्तीय क्षेत्र के संगठन अपने कामकाज के लिए परस्पर जुड़े हुए और अन्योन्याश्रित हैं। उनमें से किसी एक पर साइबर हमला पूरी वित्तीय प्रणाली को पंगु बना सकता है। इसके अलावा आज के उच्च स्तर के समन्वय के खतरे और निरंतरता से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अतीत में काम करने वाले जोखिम प्रबंधन और प्रशासन के कई पारंपरिक दृष्टिकोण आज के तेजी से बदलावों को संबोधित करने के लिए व्यापक या चुस्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, किसी भी संबंधित वित्तीय स्थिरता जोखिम को सीमित करने के लिए आरई द्वारा एक साइबर-घटना के लिए एक कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया और वसूली आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम (सी एस आई आर टी-फिन) ने सेबी को अपनी रिपोर्ट भेजी हे जिसमे में महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। विनियमित संस्थाओं को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इन सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। |  | 1. **Advisory for SEBI Regulated Entities (REs) regarding Cybersecurity best practices**   Financial sector organization are inter connected and interdependent for their functioning. Cyber-attack on any one of them might cripple the entire financial system. Further the sophistication and persistence of threat with high level of coordination among themselves, it is important to recognize that many traditional approaches to risk management and governance that worked in the past may not be comprehensive or agile enough to address the rapid changes. Thus, an efficient and effective response to and recovery from a cyber-incident by REs is essential to limit any related financial stability risks. For ensuring the same, Financial Computer Security Incident Response Team (CSIRT-Fin) has provided important recommendations in its report sent to SEBI. REs have to ensure compliance with these recommendations along with others as prescribed by SEBI from time to time. |
| *Source: SEBI/HO/ITD/ITD\_VAPT/P/CIR/2023/032 dated February 22, 2023* | | |

**हाल ही में प्रकाशित सामग्री**

**LATEST PUBLICATIONS**

1. सेबी की वार्षिक रिपोर्ट / SEBI Annual Report: 2021-22
2. भारतीय प्रतिभूति बाजार के संबंध में सांख्यिकी पुस्तिका / Handbook of Statistics on Indian Securities Market: 2020

प्रकाशित की गई सामग्री सेबी के वेबसाइट पर इस लिंक पर जाकर देखी / डाउनलोड की जा सकती है / Please visit SEBI website at the following URL to refer/download the publications: <https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics.html>

1. Keynote speech at ICRA's Conference with the theme “Decoding the key sectors that can sustain the domestic economic recovery; Sector focus- REITs, InvITs, Data Centers and NBFCs” held in Mumbai, on February 21, 2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. *In case of close ended schemes, at the time of maturity, AMC repurchases the units.* [↑](#footnote-ref-2)
3. संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर और ताइवान

   USA, France, Germany, UK, Hong Kong, South Korea, Japan, Singapore and Taiwan [↑](#footnote-ref-3)
4. यूएसए, यूके, जर्मनी, स्पेन, जापान USA, UK, Germany, Spain, Japan [↑](#footnote-ref-4)